

## महंगाई वेतन

## विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2000 से लागू दर	सं०-008 (बजट)/स०वि०उ०/कैम्प/2001, देहरादून, दिनांक-10 जनवरी, 2001	221-222
2	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2001 से लागू दर	सं०-2090 / वि०सं०शा० / 2001, देहरादून, दिनांक-28 जून, 2001	223-226
3	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2001 से लागू दर	सं० 75 / वि० अनु०-3 / 2001, देहरादून, दिनांक-24 अक्टूबर, 2001	227-228
4	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान 01 जनवरी, 2001 व 01 जुलाई, 2001 के शासनादेशों के प्रस्तर 3 में संशोधन विषयक	सं० 277 / वि० अनु०-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-01 मार्च, 2002	229-230
5	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2002 से लागू दर	सं० 413 / वि० अनु०-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-29 मई, 2002	231-232
6	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2002 से लागू दर	सं० 639 / वि० अनु०-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-18 दिसम्बर, 2002	233-236
7	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 01 जनवरी, 2001, 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जनवरी, 2002 से देय महंगाई भत्तों के शासनादेशों के प्रस्तर-3 में संशोधन विषयक	सं० 648 / वि० अनु०-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-21 दिसम्बर, 2002	237-238

8	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2003 से लागू दर	सं०-923/वि० अनु०-3/2003, देहरादून, दिनांक-16 जून, 2003	239-240
9	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 01 जनवरी, 2003 से लागू महंगाई भत्तों के शासनादेशों के प्रस्तर-3 में संशोधन विषयक	सं० 1053/वि० अनु०-3/2003, देहरादून, दिनांक-18 अक्टूबर, 2003	241-242
10	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2003 से लागू दर	सं० 1065/वि० अनु०-3/2003, देहरादून, दिनांक-24 अक्टूबर, 2003	243-244
11	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2004 से लागू दर	सं० 1261/XXVII(3)ग/2004, देहरादून, दिनांक-07 जून, 2004	245-246
12	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2004 से लागू दर	सं० 1411/XXVII(3)म/2004, देहरादून, दिनांक-02 नवम्बर, 2004	247-248
13	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू दर	सं० 174/XXVII(3)म/2005, देहरादून, दिनांक-11 मई, 2005	249-250
14	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2005 से लागू दर	सं० 09/XXVII(7)म/2005, देहरादून, दिनांक-22 अक्टूबर, 2005	251-252
15	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू दर	सं० 29/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक-26 अप्रैल, 2006	253-254
16	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जुलाई, 2006 से भुगतान	सं० 29(1)/XXVII(7)म०म०/2006, देहरादून, दिनांक-29 सितम्बर, 2006	255-256
17	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जनवरी, 2007 से भुगतान	सं० 29/XXVII(7)/2007, देहरादून, दिनांक-24 अप्रैल, 2007	257-258
18	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जुलाई,	सं० 279/XXVII(7)म०म०/2007, देहरादून, दिनांक-01 अक्टूबर, 2007	259-260

19	राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2007 से लागू दर के शासनादेश, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 के हिन्दी रूपान्तर की तृतीय पंक्ति एवं अंग्रेजी रूपान्तर की द्वितीय पंक्ति में दिनांक / Dated में संशोधन	सं०-317 / XXVII(7)पे० / 2007, देहरादून, दिनांक-15 अक्टूबर, 2007	261-262
20	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जनवरी, 2008 से भुगतान	सं० 18 / XXVII(7)म०म० / 2008, देहरादून, दिनांक-21 मार्च, 2008	263-264
21	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के क्रम में लागू महंगाई भत्ते की दरें राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना	सं० 396 / XXVII(7) / 2008, देहरादून, दिनांक-17 अक्टूबर, 2008	265-266
22	दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, निगमों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / यू०जी०सी० वेतनमान में कार्यरत पदधारकों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-07-2008 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं० 152 / XXVII(7)म०म० / 2009, देहरादून, दिनांक-27 मई, 2009	267-268
23	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं० 144 / XXVII(7)म०म० / 2009, देहरादून, दिनांक-28 मई, 2009	269-270
24	दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय / विश्वविद्यालय के शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-01-2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं० 164 / XXVII(7)म०म० / 2009, देहरादून, दिनांक-26 अगस्त, 2009	271-272
25	दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-01-2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं० 299 / XXVII(7)म०म० / 2009, देहरादून, दिनांक-15 अक्टूबर, 2009	273-274
26	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No-76 Finance Section-3/2001, Dated : Dehradun : October 24, 2001	275-276
27	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-414/Finance Section-3/2002, Dated : Dehradun : May 29, 2002	277-278
28	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-640/Finance Section-3/2002, Dated : Dehradun : December 18, 2002	279-280
29	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-924/Finance Section-3/2003, Dated : Dehradun : June 16, 2003	281-282
30	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-1066/Finance Section-3/2003, Dated : Dehradun : 24 October, 2003	283-284

31	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-1260XXVII(3)P/2004, Dated : Dehradun : 07 June, 2004	285-286
32	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1-04-04 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को मूल वेतन में आभेलेन विषयक व्यवस्था में संशोधन	सं० 1311 / XXVII(3)म०पें० / 2004, देहरादून, दिनांक-13 जुलाई, 2004	287-288
33	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1-04-04 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को मूल वेतन/पेंशन हेतु बजट आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया	सं० 1341 / XXVII(3)म०पें० / 2004, देहरादून, दिनांक-06 अगस्त, 2004	289-290
34	सेवानैवृत्तिक लाभ का समय से भुगतान, न्यायिक/विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से अदायगी के भुगतान पर ब्याज का भुगतान	सं० 979 / XXVII(3)पें० / 2004, देहरादून, दिनांक-10 अगस्त, 2004	291-294
35	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1-04-2004 से 50% महंगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन/पेंशन में विलय हेतु चिकित्सकों के एन०पी०ए० के विषय में स्पष्टीकरण एवं एक अन्य संशोधन	सं० 1358 / XXVII(3)म०पें० / 2004, देहरादून, दिनांक-27 अगस्त, 2004	295-296
36	राज्य सरकार के पेंशनर्स के पेंशन में दिनांक 1-4-2004 से 50% महंगाई राहत का मूल पेंशन में विलय विषयक कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 09 जून, 2004 का स्पष्टीकरण	सं० 1372 'A' / XXVII(3)म०पें०-5 / 2004, देहरादून, दिनांक-07 अक्टूबर, 2004	297-298
37	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-1411(1)/XXVII(3)P/2004 Dated : Dehradun :02 November, 2004	299-300
38	पेंशन की अधिकतम सीमा में वृद्धि	सं० 1425 / XXVII(3)म०रा० / 2004, देहरादून, दिनांक-11 नवम्बर, 2004	301-302
39	राज्य के पेंशनर्स की पेंशन में दिनांक 1-4-04 से 50 प्रतिशत महंगाई राहत का मूल वेतन में विलय के उपरान्त पेंशन की न्यूनतम सीमा में संशोधन के विषय में स्पष्टीकरण	सं० 75 / XXVII(3)म०पें० / 2005, देहरादून, दिनांक-17 फरवरी, 2005	303-304
40	राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु दिनांक 1-4-04 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय में आगणन विषयक	सं० 119 / XXVII(3) / (6)मा / 2005, देहरादून, दिनांक-23 मार्च, 2005	305-306
41	चिकित्सकों के एन०पी०ए० के विषय में महंगाई भत्ते के विलय की प्रक्रिया	सं० 168 / XXVII(3)म०पें० / 2005, देहरादून, दिनांक-30 अप्रैल, 2005	307-308
42	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-174(A)/XXVII(3)P/2005 Dated : Dehradun : 11 May, 2005	309-310

43	अविमाजित उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त/सेवा अवधि सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन	सं० 471/XXVII(3)/2005, देहरादून, दिनांक-07 अक्टूबर, 2005	311-312
44	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-9'A/XXVII(7)P/2005, Dated : Dehradun : 22 October, 2005	313-314
45	प्रदेश से बाहर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में महंगाई वेतन की देयता के विषय में निर्देश	सं० 01/XXVII(7)म०कि०/2006, देहरादून, दिनांक-04 अप्रैल, 2006	315-316
46	महंगाई राहत का मूल पेंशन में मर्जर की सुविधा	सं० 12/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक-15 अप्रैल, 2006	317-318
47	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-29(A)/XXVII(7)P/2006, Dated : Dehradun : 26 April, 2006	319-320
48	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रमारित अधिष्ठान की पूर्व से व्यवस्था है, के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान संदाय के सम्बन्ध में	सं० 112/XXVII(7)का०प्र०ग्रै०/2006, देहरादून, दिनांक-13 जुलाई, 2006	321-328
49	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-215/XXVII(7)P/2006, Dated : Dehradun : 04 October, 2006	329-330
50	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-30/XXVII(7)P : Dehradun : 2007, Dated : Dehradun : 24 April, 2007	331-332
51	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-280/XXVII(7)P : Dehradun : 2007, Dated : Dehradun : 01 October, 2007	333-334
52	राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय	सं० 15/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक-20 मार्च, 2008	335-336
53	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-19/XXVII(7)P 2008, Dated : Dehradun : 21 March, 2008	337-338
54	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना	सं० 420/XXVII(7)/म०रा०/2008, देहरादून, दिनांक-27 अक्टूबर, 2008	339-340
55	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-153/XXVII(7)DR/2009 Dated : Dehradun : 28 May, 2009	341-342
56	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1-1-2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण	सं० 221/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक-08 अक्टूबर, 2009	343-346

57	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1-1-2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण	सं0 305/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक-08 अक्टूबर, 2009	347-350
58	दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 297/XXVII(7)म0म0/2009, देहरादून, दिनांक-15 अक्टूबर, 2009	351-352
59	दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-01-09 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 299/XXVII(7)म0म0/2009, देहरादून, दिनांक-15 अक्टूबर, 2009	353-354
60	राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के संबंध में	सं0 310/XXVII(7)म0म0/2009, देहरादून, दिनांक-15 अक्टूबर, 2009	355-356
61	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-298/XXVII(7)DR/2009, Dated : Dehradun : 15 October, 2009	357-358

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पान्डे,  
सचिव वित्त  
उत्तरांचल शासन

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल.
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल.
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 10 जनवरी, 2001

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2000 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित:-

1. शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-377/ दस- 2000 -42(एम)/97 दिनांक 28 जुलाई, 2000
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन-एफ-सं.1(6)/ 2000- ई-11(बी)/1050, दिनांक 26 सितम्बर, 2000.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क.सं. (1) उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 1 जुलाई, 2000 से निम्नानुसार संशोधित दर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2000	वेतन का 41 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-1599/ दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-3, 4.5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क.सं.(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

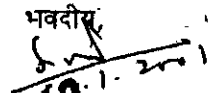
4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2000 से दिनांक 31 जनवरी, 2001 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के भविष्य निधि खाते

में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 फरवरी 2001 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो व उसे नकद दी जायेगी। मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से संबंधित बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा.4-/12-97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 फरवरी 2001 (भुगतान दिनांक 01 मार्च 2001 को देय) से नकद किया जायेगा।

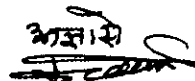
6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,  
  
 (इन्दु कुमार पाण्डे)  
 सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5-ए थानेहिल रोड, 'सत्यनिष्ठ भवन' इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न.261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा उत्तरांचल देहरादून।
6. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ट कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिबिर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चेक)।
9. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, देहरादून।
10. स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ, उ.प्र.।

अज्ञात  
  
 (के.सी. मिश्र)  
 अपर सचिव.



प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे

वित्त सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतों, उत्तरांचल।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 जून, 2001

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान 01 जनवरी, 2001 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :-

1. शासनादेश संख्या : वि०आय-व्य० 08 / सि०वि०उ० / कै / 2001, दिनांक 10 जनवरी, 2001
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय झापन एफ-1 (1)2001/ई-11 (बी) 379 दिनांक 4 अप्रैल, 2001

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 उल्लिखित शासनादेश संख्या 10 जनवरी, 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्ण कालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2001 से निम्नानुसार संशोधित दर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
जनवरी, 2001	43 प्रतिशत

2-इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या वे0आ0-1-1599/दस-42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर 3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3-ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2001 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2001 से प्रभावी महंगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आमणित किया जायेगा।

4-इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2001 से दिनांक 30 जून, 2001 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जुलाई, 2001 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी, महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा0-4-12-97-500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5-इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2001 (भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2001 को देय) से नकद किया जायेगा।

6-इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 नवम्बर, 2001 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको इस महंगाई अत्ते के बकाया, की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे  
सचिव, वित्त।

संख्या 2090/वि०सं०शा०/2001, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5ए, थार्न हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं० 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चेक)।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
10. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन सचिवालय परिसर, लखनऊ।
12. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

के०सी० मिश्र  
अपर सचिव।

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार थाण्डे,  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा 1 पें,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2-वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।

वित्त अनु भाग-3

देहरादून: दिनांक 24 अक्टूबर, 2001

विषय:-राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2001 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित:-

- 1-शासनादेश संख्या 2690/वि0सं0शा0/2001 दिनांक 28 जून, 2001।
- 2-भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन-एफ-1(6)/2001/ई-11(बी)983 दिनांक 21 सितम्बर, 2001।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0सं0-1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2001 से निम्नानुसार संशोधित दर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:

तिथि जिस दिन से देय है	प्रति माह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2001	वेतन का 45 प्रतिशत

2-इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3-ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2001 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2001 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जुलाई, 2001 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4-इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2001 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी, मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा, 4-12-97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

(2)

5-इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2002 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2002 को देय) से नकद किया जायेगा।

6-इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2002 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
सचिव, वित्त।

संख्या-75(1)/वित्त अनुभाग-3/2001 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5ए-थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
- 2-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3-वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
- 4-सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।
- 5-सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून।
- 6-निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7-रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
- 8-संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
- 9-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, देहरादून।
- 10-स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 11-पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ, उ0प्र0।
- 12-वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
- 13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुखा सचिव, वित्त ।  
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त क्वागाध्यक्ष/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
2. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3            देहरादून:            दिनांक: 01 मार्च, ,2002

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का । जनवरी, 2001 व । जुलाई, 2001 के शासनादेशों के पुस्तक 3 में संशोधन विषयक ।

-----x-----


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-75/वित्त अनुभाग-3 /2001

दिनांक 24. 10. 2001 में प्रेषण समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें उत्तरांचल.

छूट गया है। अतः शासनादेश के प्रेषण में समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उत्तरांचल धी पठा जाय ।

2. उक्त शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित सम्झा जाय।

  
इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुखा सचिव, वित्त

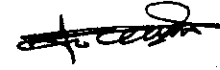
संख्या: 277 / वित्त अनुभाग-3 / 2002 / तब दिनांक: -----

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार [लिखा व इकदारी] उत्तरांचल, 5-ए धार्मिक रोड, सत्य निष्ठा एवम इलाहाबाद ।

2. निदेशक कोष्ठागार एवं वित्त सेवार्थ, उत्तरांचल देहरादून ।
3. रीजनल प्रोविडेण्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/देहरादून ।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/वेतन अनुसंधान एकक/भा./स. वित्त  
मंत्रालय/व्यय विभाग/कमरा नं. 261 नार्थ ब्लॉक, नई  
दिल्ली 110001
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



! के० सी० मिश्र !  
अपर सचिव वित्त ।

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव (वित्त),  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2-वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3-समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 29 मई, 2002

**विषय :- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2002 से लागू दर।**

पठित निम्नलिखित :-

- 1-शासनादेश संख्या 75/वित्त अनुभाग-3/2001, दिनांक 24-10-2001
- 2-शासनादेश संख्या 277/वि0अनु0-3/2002, दिनांक 01-03-2002
- 3-भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन-1(1) 2002/ई-11 (बी)/237, दिनांक 20 मार्च, 2002।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र०सं० 1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक क्रमशः 24-10-2001 एवं 01-03-2002 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू० जी० सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2002 से निम्नानुसार संशोधित दर मंहगाई भत्ते के भुगतान की संदर्भ स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2002	वेतन का 49 प्रतिशत

2-इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे० आ०-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3-ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1998 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र०सं० (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4-इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2002 से दिनांक 31 मई, 2002 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2002 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2003 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दी जायेगी, मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/रोड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा० 4-12-97-500(1)-97, दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5-इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2002 (भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2002 को देय) से नकद किया जायेगा।



6-इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-413 (1)/वि0अनु0-3/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5ए-थार्न हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय {व्यय विभाग}, कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
- 4- सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।
- 5- सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून।
- 6- निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7- रीजनल प्राविडेण्ड फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
- 8- संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ {इरला चैक}।
- 9- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
- 10- स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 11- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।
- 12- वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0 अपठनीय,  
(के0 सी0 मिश्रा),  
अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुखा सचिव,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुखा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्व विद्यालय, उत्तरांचल ।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक 18, दिसम्बर, 2002

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2002 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित:-

- 1- शासनादेश संख्या 413/वि०अनु०३/२००२ दिनांक २९ मई, २००२
- 2- भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय झाप 1/6/2002 संस्था-11/डा/789 दिनांक 30 अक्टूबर, 2002

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र. सं. 1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29 मई 2002 के क्रम में राज्यपाल महोदय, प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 1 जुलाई 2002 से निम्नानुसार संशोधित दर महंगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2002	वेतन का 52 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- वे०आ०-1-1599/दस-42/एम/97 दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 1 जुलाई 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है के मामलों में दिनांक 1 जुलाई 2002 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपरोक्त विषयांकित क्र. सं. 1/1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक

दिनांक 29 जून् 2002 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 1 जुलाई 2002 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 44 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 2 जून 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृतसंगोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 1 जुलाई 2002 से 30 नवम्बर 2002 तक की देय अवशेष धानराशि सम्बन्धित अधिकार कर्मचारी के भविष्य निधि ढाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धानराशि को भविष्य निधि ढाते में दिनांक 1 दिसम्बर 2002 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धानराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि ढाते में जमा की गई अवशेष धानराशि दिनांक 30 नवम्बर 03 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के ढाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धानराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धानराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हों वह नकद दी जायेगी, मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/गोडयूल/वालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500/1/97 दिनांक 7 अक्टूबर 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए।

5. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की पूरी हुई धानराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 दिसम्बर 2002 (भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2002) को देय से नकद किया जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिकारिता की आयु पर दिनांक 30 नवम्बर 2002 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धानराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुखा सचिव, वित्त

संख्या: 639 / वि०अनु०३/२००२ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाधी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार {लेखा एवं हकदारी} उत्तरांचल देहरादून ।
2. समस्त मुखय/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी {वेतन अनुसंधान एकक} भारत सरकार वित्त मंत्रालय {व्यय विभाग} कमरा नं० 26। नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली । 1000।
4. सचिव राज्यपाल महोदय उत्तरांचल देहरादून ।
5. सचिव विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून ।
6. निबंधाक, उच्च न्यायालय नैनीताल ।
7. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/देहरादून ।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिाविर कार्यालय नवीर कोषागार भवन {प्रथम तल} कचहरी रोड इलाहाबाद तथा अन्य विभागद्विय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ {इरला बैक}
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थें 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून ।
10. स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली ।
11. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ ।
12. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय देहरादून ।
13. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वे कृपया इस शासनादेश की पांच सौ प्रतियां मुद्रित कर वित्त अनुभाग-३ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

17/12/2002  
{रम० रम० पंत}  
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,  
अपर सचिव (वित्त),  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2-वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3-समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतों, उत्तरांचल।

देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2002

वित्त अनुभाग-3

विषय :- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 01 जनवरी, 2001, 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जनवरी, 2002 से देय मंहगाई भत्तों के शासनादेशों के प्रस्तर-3 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2690/वि0सं0शा0/2001, दिनांक 28 जून, 2001 के प्रस्तर-3 में 33 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत, शासनादेश संख्या 75/वि0 अनु0 3/2001, दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के प्रस्तर-3 में 33 के स्थान पर 37 एवं शासनादेश संख्या 413/वि0 अनु0 3/2002, दिनांक 29 मई, 2002 के प्रस्तर-3 में 33 के स्थान पर 41 प्रतिशत पढ़ा जाय। उक्त दरें केवल उन पदों के वेतनमानों में ही लागू होंगी जिनके वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं अथवा जो पुराने वेतनमान में ही विकल्प के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

2-उपरिलिखित शासनादेश केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

के0 सी0 मिश्र,  
अपर सचिव, (वित्त)।

संख्या 648 (1)/वि0अनु0 3/2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, देहरादून।
- 2-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3-वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
- 4-सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
- 5-सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6-निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7-रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
- 8-संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
- 9-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 10-स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 11-पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।
- 12-वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
- 13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र,  
अपर सचिव, (वित्त)।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून :: दिनांक:: 16 जून, 2003

**विषय-** राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2003 से लागू दर।

**पठित निम्नलिखित:-**

- 1-शासनादेश संख्या-639/विअनु-3/2002 दिनांक 18 दिसम्बर 2002
- 2-भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप 1(1)2003

संस्था-1।(ख) 284, दिनांक 04 अप्रैल, 2003

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0सं0 1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर 2002 के क्रम में राज्यपाल महोदय, ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जनवरी 2003 से निम्नानुसार संशोधित दर महँगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2003	वेतन का 55 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2003 से महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर 2002 के प्रस्तर-3 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2003 से प्रभावी महँगाई भत्ता वेतन के 44 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत/ संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी 2003 से 30 जून, 2003 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के भविष्य निधि

खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्यनिधि खाते में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से जमा माना जायेगा, और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी, और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, महँगाई भत्ते के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/ शिड्यूल /चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500(1)97, दिनांक 07 अक्टूबर 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2003 (भुगतान दिनांक 31 जुलाई, 2003 को देय) से नकद दिया जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2003 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

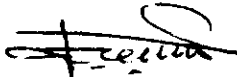
इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 923 (1)/वि0अनु-3/ 2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं०-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001।
- 4- सचिव,राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7- रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/ देहरादून।
- 8- संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतनपर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
- 9- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 10- स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 11- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।
- 12- वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय देहरादून।
- 13- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(के० सी० मिश्र),

अपर सचिव।

प्रकाश,

के० सी० मिश्र,  
अपर सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुखाकार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 18-10-2003,

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 1 जनवरी, 2003 से लागू महंगाई भत्ते के शासनादेशों के प्रस्तर-3 में संशोधन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-923/वि०अनु०3/2003 दिनांक. 16 जून, 2003 के प्रस्तर-3 में महंगाई भत्ते की दर 44 प्रतिशत के स्थान पर 47 प्रतिशत पटी जाय। उक्त दरें केवल उन पदों के वेतनमानों में ही लागू होंगी जिनके वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं अथवा जो पुराने वेतनमान में ही विकल्प के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

2. उपरिउल्लिखित शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित सम्झा

जाय।

भवदीय

॥ के० सी० मिश्र ॥  
अपर सचिव, वित्त।

संख्या: 1053 / वि०अनु०3/2003 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजात :-
1. महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून ।
  2. समस्त बरिष्ठ/कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
  3. निदेशक, उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
  4. रीजनल प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून ।
  5. स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली ।
  6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल देहरादून ।
  7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से  
॥ के० सी० मिश्र ॥  
अपर सचिव, वित्त ।



प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी / कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 24 अक्टूबर, 2003

**विषय:** राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2003 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित:-

1. शासनादेश संख्या-923/वि0अनु0-3/2003, दिनांक 16 जून, 2003
2. शासनादेश संख्या-1053/वि0अनु0-3/2003, दिनांक 18 अक्टूबर, 2003
3. भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप 1(6)2003 संस्था-II(ख) 654, दिनांक 05 सितम्बर, 2003

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या-1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 16 जून, 2003 एवं 18 अक्टूबर, 2003 के क्रम में राज्यपाल महोदय, ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0 जी0 सी0 वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2003 से नियमानुसार संशोधित दर महँगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2003	वेतन का 59 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्रम संख्या-(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 16 जून, 2003 के प्रस्तर-3 एवं दिनांक 18 अक्टूबर, 2003 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से प्रभावी महँगाई भत्ता वेतन के 51 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2003 से 30 नवम्बर, 2003 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 से जमा माना जायेगा, और इस तिथि से उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2004 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी, और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नगद दी जायेगी, महँगाई भत्ते के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/शिड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए।

5- इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 (भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2004 को देय) से नगद दिया जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाये इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1065(1)/वि0अनु0-3/2003, तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नम्बर-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001।
- 4- सचिव राजपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7- रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
- 8- संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथमतः) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
- 9- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 10- स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 11- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।
- 12- वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
- 13- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी०एन० तिह ।

अपर सचिव

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,  
अपर सचिव वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 07 जून, 2004

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2004 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :-

1. शासनादेश संख्या : 1065/वि0अनुभाग, 2001 दि0 24 अक्टूबर, 2001।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या सं0 (1)/2003-संस्था-11(ख)/दिनांक 01 मार्च, 2004।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 एवं 01 मार्च, 2004 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्ण कालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2004 से निम्नानुसार संशोधित दर महंगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2004	वेतन का 61 प्रतिशत

2-इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3-ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0 (1) व (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से प्रभावी महंगाई भत्ता वेतन के 53 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जावेगा।

4-इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जुलाई, 2004 से जमा माना जायेगा, और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक जुलाई, 2005 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा0-4-12-97-500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5-इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2004 (भुगतान दिनांक 31 2004 को देय) से नकद किया जायेगा।

6-इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

एल0एम0 पन्त,

अपर सचिव।

संख्या 1261/XXVII(3)ग/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं० 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
7. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. उप निदेशक, राजकीयमुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां तत्काल मुद्रित कर वित्त अनुभाग को उपलब्ध कराने
11. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

एल0एम0 पन्त,

अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूडी  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक 02 नवम्बर, 2004

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2004 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-1261/XXVII(3)म/2004, दिनांक 07 जून, 2004
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-फा0सं01(2)/2004, संस्था-11(ख)/625.22 सितम्बर, 2004।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07 जून, 2004 एवं 22 सितम्बर, 2004 के पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-1267/XXVII(3)म0पें/2004, दिनांक 09 जून, 2004 के द्वारा 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय कर दिया गया था और उसके बाद 11 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता देया था, के कम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2004 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2004	वेतन का 14 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2004 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्रमांक-(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07 जून, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जुलाई, 2004 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 56 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4- इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2004 से 31 अक्टूबर, 2004 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 नवम्बर, 2004 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर,2005 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो,वह नकद दी जायेगी,बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 नवम्बर,2004(भुगतान दिनांक 30 नवम्बर,2004 को देय) से नकद किया जायेगा।

6- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च,2005 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों,उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी  
सचिव।

संख्या : 1411 / XXVII(3)म/2004, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनेार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक 11 मई, 2005

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-1411/XXVII(3)म/2004, दिनांक 02 नवम्बर, 2004
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-फा0सं01(1)/2005, संस्था-11(ख)/263, दिनांक 31 मार्च, 2005।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र० सं० 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 एवं 31 मार्च, 2005 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2005 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2005	वेतन का 17 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्रमांक-(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जनवरी, 2005 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 59 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4- इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 31 मई, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2005 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2006 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500(1)97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2005 (भुगतान दिनांक 30 जून, 2005 को देय) से नकद किया जायेगा।

6- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 मई, 2005 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,  
(राधा रतूड़ी)  
सचिव।

संख्या : 11 / XXVII(3)म/2005, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।



प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य नियम - वेतन आयोग) अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक : 01 जुलाई, 2005 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-174 / XXVII(3)म/2004, दिनांक : 11 मई, 2004
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-फा0सं01(5)/2005, संस्था-11(ख)/746, दिनांक : 07 अक्टूबर, 2005।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक : 11 मई, 2005 एवं 07 अक्टूबर, 2005 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक : 01 जुलाई, 2005 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2005	वेतन का 21 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक : 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक : 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक : 01 जनवरी, 2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्रमांक-(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जुलाई, 2005 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 63 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4- इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक : 01 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

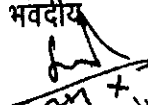
जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक : 01 नवम्बर, 2005 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक : 31 अक्टूबर, 2006 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500(1)97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक : 01 नवम्बर, 2005 (भुगतान दिनांक 30 नवम्बर, 2005 को देय) से नकद किया जायेगा।

6- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक : 30 अक्टूबर, 2005 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय  
  
(इन्दु कुमीर पाण्डे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 09 (1)/XXVII(7)म/2005, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2- वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त (वि0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक 26 अप्रैल, 2006

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-09/XXVII(7)म/2005, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-फा0सं01(2)/2006, संस्था-II(ख)/166, दिनांक 29 मार्च, 2006।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 एवं 29 मार्च, 2006 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2006	वेतन का 24 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01.07.2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित कमांक (1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 66 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4- इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 अप्रैल, 2006 तक देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

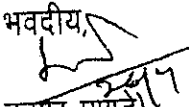
जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 मई, 2006 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500(1)97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 मई, 2006 (भुगतान दिनांक 31 मई, 2006 को देय) से नकद किया जायेगा।

6- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।


7- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2006 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,  
  
(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 29 (1) / XXVII (7) म / 2006, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से  
  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2-वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 3-समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त (सा०नि०-वे०आ०)अनुभाग-7, देहरादून : दिनांक 29 सितम्बर, 2006

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2006 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित :-

- 1-शासनादेश संख्या-29/XXVII(7)/2006, दिनांक 26 अप्रैल, 2006
- 2-भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(13)/2006-संस्था-II(ख)/523, दिनांक 11 सितम्बर, 2006

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रमांक-1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 26 अप्रैल, 2006 तथा दिनांक 11 सितम्बर, 2006 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2006 से महंगाई भत्ता 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2006 से, उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को देय धनराशि नकद में भुगतान की जायेगी परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बन्धी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4- इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

5- ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण में दिनांक 01 जुलाई, 2006 से महंगाई भत्ता वेतन के 71 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीय

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-29(1)(1)/XXVII(7)/म0भ0/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
- 4- सचिव, राज्यपाल महोदय उत्तरांचल, देहरादून।
- 5- सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून।
- 6- महा निबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 7- रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
- 8- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, देहरादून।
- 9- स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी / कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक: 24 अप्रैल, 2007

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-29 (1)/ XXVII (7) म0म0/2006, दिनांक 29 सितम्बर, 2006.
- 2- भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(2)/2007.  
संस्था-II(ख)/64 दिनांक 22 मार्च, 2007.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2006 एवं दिनांक 22 मार्च, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से महंगाई भत्ता 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2007 से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बन्धी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4- उक्त कर्मचारियों को छोड़कर शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को इस शासनादेशों द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक, 01 जनवरी, 2007, से 30 अप्रैल, 2007 तक देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 मई, 2007 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 अप्रैल, 2008 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसी


उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये। स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 मई, 2007 (भुगतान दिनांक 31 मई, 2007 को देय) से नकद किया जायेगा।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तारों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

6- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण में दिनांक 1 जनवरी 2007 से महगाई भत्ता वेतन के 77 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

7-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2007 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।


भवदीया,

  
राधा रतूडी  
सचिव।

संख्या : (1) / XXVII(7)म/2007, एवं तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/ देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, एकक देहरादून।

आज्ञा से,

  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।



प्रेषक,

राधा रतूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7

देहरादून:दिनांक 01 अक्टूबर, 2007

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई 2007 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित:-

- 1-शासनादेश संख्या-29/XXVII(7)/2007, दिनांक 24 अप्रैल, 2007.
- 2-भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(8)/2007 संस्था-II(ख)/212 दिनांक:11 सितम्बर, 2007.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं01 एवं 2में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2007 एवं दिनांक: 11 सितम्बर, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांक: 01 जुलाई 2007 से मंहगाई भत्ता 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 41 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत /संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक: 01 जुलाई 2007, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को देय धनराशि नकद भुगतान की जायेगी परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बन्धी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4- इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

5- ऐसे अधिकारियों /कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण में दिनांक 01 जुलाई, 2007 से मंहगाई भत्ता, वेतन के 83 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूडी)  
सचिव वित्त।

संख्या 279(U)/XXVII(7)/2007, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/ देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,  
7/11/07  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त: (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7

देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत का भुगतान दिनांक: 01 जुलाई, 2007 से लागू दर के शासनादेश दिनांक: 01 अक्टूबर, 2007 के हिन्दी रूपान्तर की तृतीय पंक्ति एवं अंग्रेजी रूपान्तर की द्वितीय पंक्ति में "दिनांक/ Dated" में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त निम्न शासनादेश संख्या: 280/XXVII(7)पें./2007 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2007 के हिन्दी रूपान्तर की तृतीय पंक्ति में दिनांक "04 अक्टूबर, 2007" एवं अंग्रेजी रूपान्तर की द्वितीय पंक्ति में "Dated: 30 April, 2007" त्रुटिवश अंकित हो गया है। अतः इसे अब उक्त के स्थान पर हिन्दी रूपान्तर में दिनांक "24 अप्रैल, 2007" एवं अंग्रेजी रूपान्तर में "Dated: 24 April, 2007" पढ़ा जाय।

2. उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 317/XXVII(7)पें./2007, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261 नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/ देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से  
TJ/a  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी / कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 21 मार्च, 2008

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी 2008 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित:-

- 1- शासनादेश संख्या-279/XXVII(7)म.भ./2008, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007.
- 2- भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(1)/2008 संस्था-II (ख) / दिनांक: 17 मार्च, 2008.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र० सं० 01 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 एवं दिनांक: 17 मार्च, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांक: 01 जनवरी, 2008 से मंहगाई भत्ता 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

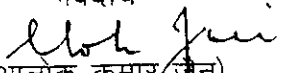
2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबन्ध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक: 01 जनवरी, 2008, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2008 से दिनांक 31 मार्च, 2008 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अप्रैल, 2008 का वेतन देय 30 अप्रैल, 2008, से वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बन्धी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4- इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

5- ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी, 2008 से मंहगाई भत्ता, वेतन के 89 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीय

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या 18 /XXVII(7)/2008, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर / देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या:396 / XXvii(7) / 2008  
देहरादून:दिनांक:17 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के कम में लागू मंहगाई भत्ते की दरें राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिये जाने विषयक राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में निर्गत शासनादेश संख्या395 / XXvii(7) / 2008दिनांक:17अक्टूबर / 2008 द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों पर निम्नानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराया जाय:-

मंहगाई भत्ते की दरें लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य कुल मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
1-1-2006से	मंहगाई भत्ता देय नहीं है
1-7-2006 से	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1-1-2007से	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1-7-2007 से	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1-1-2008 से	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1-7-2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

2- उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या संख्या: 29 / XXvii(7) / 2006 दिनांक 26 अप्रैल, 2006 द्वारा दिनांक 1-1-2006 से शासनादेश संख्या 29(1) / XXvii(7) / 2006 दिनांक 29 सितम्बर 2006, द्वारा दिनांक 1-7-2006से शासनादेश संख्या 29 / XXvii(7) / 2007 दिनांक 24 अप्रैल 2007 द्वारा 1-1-2007 से एवं शासनादेश संख्या 279 / XXvii (7) मं0 भ0 / 2007 दिनांक 1अक्टूबर 2007 द्वारा दिनांक 1-7-2007 से, शासनादेश संख्या 18 / XXvii(7)मं0भ0 / 2008 दिनांक 21 मार्च 2008 द्वारा दिनांक 1-1-2008 से स्वीकृत किये गये मंहगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरान्त किया जाएगा ।

3- दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड-वेतन को जोड़कर

जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा । इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4-मंहगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत की स्वतन्त्र अनुमन्यता है, इसे मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा ।

5-मंहगाई भत्ते के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे अगले रूपये में मान लिया जाय ।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या:398(1)/XXvii(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
- 3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
- 4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
- 5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- 6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
- 7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 11.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
- 12.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)  
अपर सचिव ।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 21 मई, 2009

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत पदधारकों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-07-2008 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:18/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 21 मार्च, 2008।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-EII(B) दिनांक 3 अक्टूबर, 2008,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों पर दिनांक 1-7-2008 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य है, परन्तु जिन कर्मचारियों को अभी पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है उन्हें दिनांक 1-1-2008 से 47 प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य है किन्तु दिनांक 1-7-2008 से उक्त श्रेणी के कर्मचारियों बढी हुयी दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं हुआ है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 21 मार्च, 2008 एवं 3 अक्टूबर, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत पदधारकों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांक 01-07-2008 से मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2008, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 31 मई, 2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जून, 2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोजकों के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)



संख्या : / xxvii(7)म.भ./2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),  
कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा (से,  
टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी / कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 28 मई, 2009

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या:1(1)/2009-संस्था-II(ख) दिनांक 13 मार्च, 2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के शासनादेश संख्या 396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिनांक 1-7-2008 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या:396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या:1(1)/2009-संस्था-II(ख) दिनांक 13 मार्च, 2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-1-2009 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2009 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जून, 2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियुक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)  
सचिव।

संख्या : 144 / xxvii(7)म.भ. / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),  
कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव।

प्रेषक,

टी०एन०सिंह

अपर सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-7

देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2009

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-01-2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या: 152/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 27मई, 2009।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-EII(ख) दिनांक 19 मार्च, 2009।

महोदय,

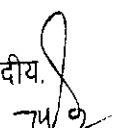
उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे०आ०-सा०नि०) अनु०-7 के शासनादेश संख्या संख्या: 152/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 27मई, 2009 द्वारा दिनांक 1-1-2008 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 54 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 27मई, 2009 एवं 19मार्च, 2009 के क्रम में दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांक: 01-01-2009 से मंहगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 64 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31मई, 2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जून, 2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन०एस०सी० के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

  
(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव।

संख्या : 164 / xxvii(7)म.भ. / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),  
कुमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

टी0एन0सिंह  
अपर सचिव,वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून,दिनांक।5 अक्टूबर, 2009

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-01-2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:164/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009।
- 2- भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-EII(बी) दिनांक 29 सितम्बर,2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मिकों को वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश संख्या संख्या:164/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009 द्वारा दिनांक 1-1-2009 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 64 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 26 अगस्त,2009 एवं 29सितम्बर,2009 के कम में दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांक: 01-07-2009 से मंहगाई भत्ते को 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई 2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2009 से 31 अक्टूबर,2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01नवम्बर,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियुक्त के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव।

संख्या : 299 / xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),  
कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

11 - प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम 3/2/2009 21/1/10

आज्ञा से.  
-11/2-  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

Government of Uttaranchal  
Finance Section-3

No-76-Finance Section-3/2001  
Dated: Dehradun: October 24, 2001

**Office Memorandum**

**Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Civil/  
Family Pensioners**

The undersigned is directed to refer to this office Memo No. 6047/Vi Sa V/2001, Dated June 30, 2001 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from Jan 1, 2001 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/Family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 2% (Two Percent) with effect from July 01, 2001 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated June 30, 2001 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of pension/Family Pension w.e.f. 01.07.2001 has risen to 45%.

2- Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of who separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical "Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5- As per order issued in O.M. No. A-I-252/X-10(3)-81, dated April, 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the authorities/Public Sector Banks.



6- Other terms and conditions regarding grant of Dearness Relief laid down in earlier Government order shall remain applicable as usual.

INDU KUMAR PANDEY  
Secretary

**No. 76Vitt. Anu-3/2001 the dated**

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal
- 2- All Heads of Departments/Offices, Uttaranchal.
- 3- Regional Addl. Director Treasury and Pension, Garhwal/Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
- 5- All Treasury Officers, Uttaranchal.
- 6- Accountant General U.P. and Uttanchal, 5A- Thorn Hill Road, Satynishtha Bhawan, Allahabad alongwith 50 extra Copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
- 7- Depute Director, Govt. Press Roorkee with the request that 1000 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt Please.

By Order,

K.C. Misra  
Addl. Secretary

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3

संख्या 414/वि0अ0-3/2002  
देहरादून: दिनांक 29 मई, 2002.

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों  
आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह  
कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3,  
उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 76/वि0  
अ0-3/2001, दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के द्वारा  
मंहगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2001 से  
स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने  
राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक  
पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई  
वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक  
01 जुलाई, 2001 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण  
करते हुए 01 जनवरी, 2002 से मंहगाई राहत की  
एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये  
जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार  
दिनांक 01 जनवरी, 2002 से राहत की दर बढ़कर  
49 प्रतिशत हो गई है।

2-मंहगाई राहत की ऐसी घनराशि जो एक  
रुपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रुपये  
में राउण्ड कर दिया जाय।

3-यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक  
सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय  
निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों  
पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों  
द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित  
होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग  
के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण  
संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों,  
जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक  
पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए-1-252/  
दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत  
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के  
भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की  
आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/  
सार्वजनिक बैंकों पर इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत  
मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal  
Finance Section-3

No. 414/Fin.Sec.-3/2002  
Dated: Dehradun May 29, 2002

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State  
Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this  
office memo No. 76/Vitt.Anu-3/2001, dated  
October 24, 2001 on the subject mentioned above  
sanctioning on the subject mentioned above  
sanctioning an instalment of Dearness Relief with  
effect from July 1, 2001 and to say that the Govern-  
or is pleased to revise the rates of Dearness  
Relief admissible to all Civil/Family pensioners  
of this Government to Compensate them for the  
rise in the cost of living beyond average consumer  
price index 306.33 (as on 1-1-1996) at the rate of  
4% (Four Per cent) with effect from January 01,  
2002 in supersession of the rates mentioned in the  
O.M. dated 25-9-2001 referred to above accordingly  
the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pen-  
sion w.e.f. 01-01-2002 has risen to 49%.

2. Payment of Dearness Relief involving a  
fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher  
rupee.

3. These orders will not be applicable to the  
Judges of High Court, Chairman and Members of  
Uttaranchal Public Service Commission, employees  
of local bodies and Public undertakings/Corporation  
etc. in respect of whom separate orders will have to be  
issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such  
teaching and non-teaching pensioners of Institutions  
aided from State under the education/Technical Edu-  
cation Department whose pension/Family pension is  
at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.No. A-1-  
252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Account-  
ant General Authority is not necessary for pay-  
ment of relief of pension and as such the pay-  
ment of dearness relief as admissible under, this  
O.M. shall be made by the paying authorities/  
Public Sector Banks.

6-महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव।

INDU KUMAR PANDE,  
Principal Secretary.

संख्या 414(1)/वि0अ0-3/2002 तद्दिनांक

No. 414(1)/Fm.Sec.-3/2002 the dated

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

Copy forwarded to following for information and necessary action :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
  - 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
  - 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
  - 4-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ, उत्तरांचल।
  - 5-महालेखाकार, उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल, 5-ए, थार्न-हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  - 6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
1. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal.
  2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
  3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
  4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
  5. Accountant General U.P. and Uttaranchal 5-A Thorn Hill Road, Satyanistha Bhawan, Allahabad alongwith 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
  6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

आज्ञा से,

By Orders,

(के0 सी0 मिश्रा)  
अपर सचिव।

(K.C. MISHRA)  
Addl. Secretary.

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-3

संख्या 640/वि0अनु0-3/2002

देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 414/वि0अनु0-3/2002, दिनांक 29 मई, 2002 के द्वारा मंहगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2002 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 जनवरी, 2002 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2002 से मंहगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2002 से राहत की दर बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है।

2-मंहगाई राहत की ऐसी घनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3-यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 07 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal

Finance Section-3

No. 640/Fin.Sec.-3/2002

Dated Dehradun, December 18, 2002

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo no. 414/Vitta.Anu-3/2002, dated May 29, 2002 on the subject mentioned above sanctioning on instalment of Dearness Relief with effect from January 01, 2002 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/Family Pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 01-01-1996) at the rate of 3% (Three Per cent) with effect from January 01, 2002 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated 29-05-2002 referred to above accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2002 has risen to 52%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 07, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying Authorities/Public Sector Banks.

6-मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,  
इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 640/वि0अनु0-3/2002. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
- 4-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- 5-महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,  
एल0 एम0 पन्त,  
अपर सचिव।

6. Other terms and conditions regarding of dear-ness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

By Order,  
INDU KUMAR PANDE,  
Principal Secretary.

No. 640/Fin Sec.-3/2002, the dated

*Copy forwarded to following for information and necessary action :-*

1. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal.
2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun alongwith 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

By Order,  
L. M. PANT,  
Addl. Secretary.

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या-924 / वि०अनु०-3 / 2003  
देहरादून : दिनांक : 16 जून, 2003

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-640/वि०अनु०-3/2002 दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2002 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपरोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुये 01 जनवरी, 2003 से महंगाई राहत की एक और किश्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2003 से राहत की दर बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-ए-1-252/दस-10(3)-81 दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal  
Finance Section-3  
No- 924 /Fin.Sec.-3/2003  
Dated : 16 June, 2003

Office Memorandum

**Subject:** Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No 640/Vitt. Anu-3/2002 dated 18 December 2002 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1 July 2002 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/ Family pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.33 ( as on 1.1.1996) at the rate of 3%(percent) with effect from 01 January, 2003 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 29.5.2002 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2003 has risen to 55%.

2- Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service commission, employees of local bodies and Public undertaking/ Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/x-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव

Indu Kumar Pande  
Principal Secretary

संख्या १२४/वि०अनु०-३/२००३/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

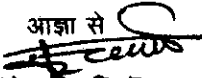
3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल मण्डल/कुमायें मण्डल।

4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओवेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से  
  
(के० सी० मिश्र)  
अपर सचिव।

No १२४/Fin.Sec.-3/2003 the date

Copy forwarded to following for information and necessary action:

1. All Principal Secretaries/ Secretaries. Government of Uttaranchal.

2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.


3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.

4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.

5. Accountant General Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other States be also informed please.

6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

7. Deputy Director, Govt. Press Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

By order  
  
(K.C. Misra)  
Addl. Secretary

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या-1064/वि0अनु0-3/2003  
देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2003

कार्यालय-ज्ञाप

Government of Uttaranchal  
Finance Section-3  
No-1066/Fin.Sec.-3/2003  
Dated : 24 October, 2003

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों  
आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**Subject:** Grant of Dearness Relief to State  
Government Civil/Family pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का  
निर्देश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन के  
कार्यालय ज्ञाप संख्या-924/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 16  
जून, 2003 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी,  
2003 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने  
राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक  
पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की  
प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 जून, 2003 में  
उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुये 01 जुलाई, 2003  
से महंगाई राहत की एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार  
प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती  
है। तदनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2003 से राहत की दर  
बढ़कर 59 प्रतिशत हो गई है।

The Undersigned is directed to refer to  
this office memo No-924/Vitt. Anu-3/2002  
dated 16 June, 2003 on the subject mentioned  
above sanctioning an instalment of Dearness  
Relief with effect from 1 January, 2003 and  
to say that the Governor is pleased to revise  
the rates of Dearness Relief admissible to all  
Civil/ Family pensioners of this Government  
to Compensate them for the rise in the cost of  
living beyond average consumer price index  
306.33 ( as on 1.1.1996) at the rate of  
4%(percent) with effect from 01 July, 2003  
in super session of the rates mentioned in the  
O.M. dated 16.06.2003 referred to above  
accordingly the rate of dearness of  
pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2003  
has risen to 59%.

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये  
से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड  
कर दिया जाय।

2- Payment of Dearness relief involving  
a fraction of a rupee shall be rounded, off to  
next higher rupee.

3- यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा  
आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा  
सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे,  
उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश  
निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3- These orders will not be applicable to  
the Judges of High Court, Chairman and  
Members of Uttaranchal Public Service  
commission, employees of local bodies and  
Public undertaking/ Corporation etc. in  
respect of whom separate orders will have to  
be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के  
अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के  
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों  
के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू  
होंगे।

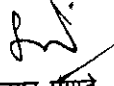
4- These order will also be applicable to  
such teaching and non-teaching pensioners of  
Institutions aided from State under the  
education/Technical Education Department  
whose Pension/Family pension is at par with  
the pensioners of the State Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप  
सं0-ए-1-252/दस-10(3)-81 दिनांक 27 अप्रैल, 1982  
में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के  
भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की  
आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत  
महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

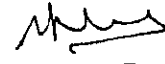
5- As per orders issued in O.M. No. A-  
1-252/x-10(3)-81 dated April 27, 1982 the  
Accountant General Authority is not  
necessary for payment of relief of pension  
and as such the payment of dearness relief as  
admissible under, this O.M. shall be made by  
the paying authorities/ Public Sector Banks.



6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।


  
इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

  
(Indu Kumar Pande)  
Principal Secretary

संख्या-1066/वि0अनु0-3/2003 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :


- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल मण्डल/कुमायें मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- 5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओवेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से  
  
टी.एन. सिंह  
अपर सचिव।

No. 1066/Fin.Sec.-3/2003 the date

Copy forwarded to following for information and necessary action:

1. All Principal Secretaries/ Secretaries. Government of Uttaranchal.
2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Deputy Director, Govt. Press Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

By order  
  
(T.N. Singh)  
Add. Secretary

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या- 1260 XXVII(3)पे0/2004  
देहरादून:दिनांक 27 जून, 2004  
कार्यालय-ज्ञाप

Government of Uttaranchal  
Finance Section-3  
NO- 1260 / XXVII(3)P/2004  
Dehradun: Dated 27 June, 2004

**Office Memorandum**

**विषय:-राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों  
आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**Subject: Grant of Dearness Relief to state  
Government civil/ family pensioners.**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग- 3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1066/वि0 अनु0-3/2003, दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2003 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2004 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2004 से राहत की दर बढ़कर 61 प्रतिशत हो गई है।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-1066/ Vitt.Anu-3/2003, dated 24 October, 2003 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2003 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 2% (percent) with effect from 01 July, 2004 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 24-10-2003 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2004 has risen to 61%.

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- यह आदेश न्यायालय के न्यायिधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service commission, employees of local bodies and Public undertaking/ corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

4- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/ Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

5- As per orders issued in O.M. NoA-1-252/X-10(3)-81 dated April 27 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(एल०एम०पंत)  
अपर सचिव

(L.M.Pant)  
Addl. Secretary

1260  
संख्या- XXVII(3)P/2004, तददिनांक।

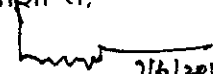
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

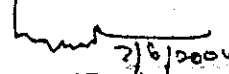
- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- 5-महोलेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7-उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

No-1260/XXVII(3)P/2004, the date.

copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1-All Principal Secretaries/ Secretaries, Government of Uttaranchal.
- 2-All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
- 3-Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4-Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
- 5-Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Mazra, Dehradun. along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
- 7-Deputy Director, Govt.Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

आज्ञा से,  
  
(एल०एम०पंत) 2/6/2004  
अपर सचिव

By Order,  
  
(L.M.Pant) 2/6/2004  
Addl. Secretary

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-3

संख्या-1311 XXVII(3)म-पें/2004

देहरादून:दिनांक 13 जुलाई,2004

कार्यालय-ज्ञाप

**विषय :** राज्य सरकार के कर्मचारियों /पेंशनर्स के वेतन/ पेंशन में दिनांक 1.4.04 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता /मंहगाई राहत को मूल वेतन में आमेलन विषयक व्यवस्था में संशोधन ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267- XXVII(3)म-पें/2004 ,दिनांक 9 जून,2004के द्वारा 1.4.04 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता /मंहगाई राहत का मूल वेतन में आमेलन की व्यवस्था किए जाने के उपरान्त प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न सेवा संघों के द्वारा उक्त शासनादेश में कतिपय संशोधन किए जाने की मांगों पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2 में मूल वेतन मे विलय किए गये उक्त मंहगाई भत्ते को सेवानैवृत्तिक लाभ,सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए आगणित किए जाने की व्यवस्था को संशोधित करते हुए इसे अब केवल सेवानैवृत्तिक लाभ एवं विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए ही आगणित किए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं अर्थात उक्त आमेलित मूल वेतन को सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए आगणित नहीं किया जायेगा और कर्मी द्वारा प्राप्त हो रहे मूल वेतन के आधार पर ही उक्त अंशदान में कटौती पूर्ववत् की जायेगी ।

2.उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 केवल उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत लागू रहेंगे

राधा रतूड़ी

सचिव,वित्त ।

1311

संख्या- XXVII(3)पें/2004,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
- 3 सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल देहरादून ।
- 4 सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून ।

5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/ कुमाऊ मण्डल ।
9. महोलखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/ देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी/ कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
13. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियों मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
14. निदेशक एन0आई0सी0, देहरादून ।

आज्ञा से,



(रमेश चन्द्र शर्मा)

उप सचिव, वित्त ।

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1.4.2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन/पेंशन हेतु बजट आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया।

राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1 अप्रैल 2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन में विलय करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/XXV ii (3)मं0पें0/2004 दिनांक 6 जून 2004 के प्रस्तर-8 में धनराशि के आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मंहगाई वेतन/मंहगाई पेंशन के विषय में बजट आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

- 1- मंहगाई वेतन का भुगतान आय व्ययक में खोली गयी मानक मद 48-मंहगाई वेतन में किया जायेगा जिसे विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर अविलम्ब रख दिया जायेगा।
- 2- पेंशन भोगियों को मंहगाई पेंशन का भुगतान संगत विस्तृत हेड में 49-मंहगाई पेंशन मद में प्राविधानित धनराशि से भुगतान किया जायेगा।
- 3- कर्मचारियों को देय सकल वेतन की बचनबद्ध मदों यथा 01- वेतन, 03-मंहगाई भत्ता, 06-अन्य भत्ते एवं 48-मंहगाई वेतन में प्राविधानित धनराशि का योग करते हुये धनराशि उपलब्ध है तो उक्त मदों में से किसी भी यथावश्यक मद में धनराशि का उपयोग सकल वेतन के भुगतान हेतु कोषागार द्वारा भुगतान हेतु देयक स्वीकार किया जायेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में पेंशन के विस्तृत हेड में खुली मानक मदें 33-पेंशन/अनुतोषिक एवं 49-मंहगाई पेंशन के विषय में होगी। बजट नियंत्रक अधिकारी / प्रशासनिक विभाग वेतन सम्बन्धी मदों में बचत / व्ययाधिक्य के प्रकरण का अन्तिम समायोजन पुनर्विनियोग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथासमय करेंगे तथा उसकी प्रति महालेखाकार एवं सम्बन्धित प्राधिकारी / कोषागार को भी भेजी जायेगी।
- 4- जिन विभागों में अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) की योजना लागू है उन विभागों में दिनांक 1.4.2004 से मूल वेतन में 50% मंहगाई भत्ते को विलय करने के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के अनुसार ही अंशदायी भविष्य निधि का अंशदान नियोक्ता एवं कर्मचारी के वेतन से काटा जायेगा।
- 5- शासनादेश संख्या-(449/04)/ 248/नौ-3-ऊ0/पेंशन /02 दिनांक 9 मार्च, 2004 के द्वारा विद्युत परिषद के पेंशन से जिनका भुगतान कोषागार से किया जा रहा है के लिये भी मंहगाई वेतन की वही व्यवस्था होगी जो राज्य सरकार के कर्मियों के सम्बन्ध में है निदेशक, लेखा एवं हकदारी द्वारा इस श्रेणी के पेंशनर्स हेतु अनन्तिम पेंशन के विषय में उसी प्रकार से निश्चित

अवधि का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा। जैसा नियमित अवधि के लिय पी०पी०ओ० निर्गत होता है।

- 6- जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों में 50%मंहगाई वेतन को जोड़ कर पेंशन की गणना की गयी है, उसका स्पष्ट उल्लेख पृथक से पेंशन भुगतानादेश में किया जाये, ताकि कोषागार स्तर से पेंशन में 50 प्रतिशत मंहगाई राहत जोड़ कर निर्धारण न किया जा सके।
- 7- 1-4-2004 से मंहगाई वेतन/मंहगाई पेंशन (50 प्रतिशत) के सामायोजन के बाद देय मंहगाई भत्ता/ मंहगाई राहत (1-4-2004 को मात्र 11 प्रतिशत) का ही भुगतान किया जाये। जिन प्रकरणों में दिनांक 1-4-2004 के बाद 61 प्रतिशत मंहगाई भत्ता / मंहगाई राहत भुगतान किया गया हो उसे पुनः निर्धारण कर मंहगाई वेतन/ मंहगाई पेंशन को मंहगाई भत्ते/ मंहगाई राहत का निर्धारण एवं भुगतान किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार बजट आवंटन एवं भुगतान की कार्यवाही अपने स्तर से अविनम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

राधा रतूडी  
सचिव, वित्त

संख्या /xxii(3)म०पें०/2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
- 3- सचिव राज्यपाल महोदय उत्तरांचल, देहरादून ।
- 4- सचिव विधन सभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 5- महानिबंधक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
- 6- निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
- 8- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल ।
- 9- महालेखाकार, उत्तरांचल, औबराय भवन, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10- रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर / देहरादून ।
- 11- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 12- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
- 13- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 14- निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून ।

आज्ञा से,

( टी०एन० सिंह )  
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख राधिय  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं  
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष  
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 10 अगस्त, 2004

विषय:-सेवानिवृत्तिक लाभ का समय से भुगतान, न्यायिक/विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से अदायगी के भुगतान पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किए गये है। प्रशासनिक कारणों से "ग्रेच्युटी" की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-सा-3-684/दस-971/80 दिनांक 29.04.1983, शासनादेश संख्या-सा-3-1778/दस-971/80 दिनांक 30-11-1984 शासनादेश संख्या-सा-3-2102/दस-971/80 दिनांक 08-12-1994 एवं अर्धशासकीय पत्र संख्या-सी-3-002/दस-99-303/99 दिनांक 28-9-1999 द्वारा निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्युटी पर ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गई है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः ग्रेच्युटी पर तीन माह से अधिक विलम्ब पर भुगतान की अवधि में नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर के समान होगी।

3. जिन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायिक/विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में विलम्ब हो जाता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा, इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोन्मुख मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि:-

- (1) यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरुद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में यदि ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि बड़ी होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं। जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरुद्ध चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि से ग्रेच्युटी की अनुमन्यता मानी जायेगी और ऐसे तीन



माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु ब्याज अनुमन्य हो जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चलते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तथा मात्र मृत्यु के कारण विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त की जाती है, ऐसे प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

- (2) उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णीत नहीं हो सके हैं, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुनर्उद्घाटित नहीं किया जायेगा।
- (3) सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गये हैं। सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तरांचल पेन्शन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) उत्तरांचल नियमावली, 2003 अधिसूचना संख्या-1033/वित्त अनु0-4/2003, दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को निर्गत की जा चुकी है। उक्त नियमावली में पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जाय तथा यदि पेन्शन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उस स्थिति में अनन्तिम पेन्शन का भुगतान किया जाय। यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को नहीं हो सके तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो जाने के कारणों सहित उच्चतर अधिकारी को दिया जाना अवैधित होगा, जो पेन्शन प्रकरण का सीधे निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

4. यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्यूटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह के अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा। यदि यह निर्णीत हो जाता है कि ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाना है तो प्रशासक भुगतान तुरन्त कर दिया जाय और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय। ऐसा करने से ब्याज की मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी। परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जायेगा जहाँ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो। ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उनके वेतन के अनुपात में की जाये।

5. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा अपनी पेन्शन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर यदि ब्याज की मांग करते हैं तब ऐसे प्रकरणों हेतु स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि पेन्शन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पेन्शन एवं देय महंगाई राहत का भुगतान होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी को

वानिवृत्ति की तिथि को उसके विरुद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उस कार्यवाही के अन्तर्गत रहते पेन्शन के एक भाग का शशिकरण अनुपान्य नहीं होगा।

कृपया उपरोक्त प्रस्तरी में स्पष्ट की गयी स्थिति का कठार्ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या-979/Xxvii (3) पे/2004, तददिनांकित.

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून।
2. निदेशक, पेन्शन एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरीय भवन, गाजरा, देहरादून.
4. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. विधान सभा, सचिवालय।
8. राज्यपाल सचिवालय।
9. गार्ड फाईल।

10. निदेशक (पेन्शन) आओ सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से



(टी०एन० सिंह)  
अपर सचिव, वित्त

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3

संख्या 1358/XXVII(3) मं0पें0/2004

देहरादून : दिनांक 27, अगस्त, 2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1-4-2004 से 50 % मंहगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन/पेंशन में विलय हेतु चिकित्सकों के एन0पी0ए0 के विषय में स्पष्टीकरण एवं एक अन्य संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267-XXVII(3) मं0पें0/2004 दिनांक 9जून,2004द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों/पेंशनर्स के मूल वेतन में मंहगाई भत्ता/राहत का 50% जोड़े जाने के विषय में निर्गत दिशानिर्देशों के उपरान्त चिकित्सक संवर्ग में चिकित्सकों को अनुमन्य एन0पी0ए0को मूल वेतन अथवा मूल वेतन के साथ 50% मंहगाई भत्ते के आमेलन के विषय में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने हेतु कोषागार एवं उक्त संवर्ग से ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

2- उक्त प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0पी0ए0, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 के भाग 2-4 के मूल नियम 9(21)(1) के अनुसार वेतन का ही भाग होता है और कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून, 2004 के द्वारा लागू व्यवस्था के उपरान्त चिकित्सकों को एन0पी0ए0 का भुगतान मूल वेतन में 50% आमेलित मंहगाई वेतन के अनुसार अनुमन्य प्रतिशत के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। इसके आगणन हेतु उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

मूल वेतन	रू0 10,000
मंहगाई वेतन(मूल वेतन का 50%)	रू0 5,000
	-----
	रू0 15,000
एन0पी0ए0(मूल वेतन का 20%)	रू0 3,000
	-----
	रू0 18,000
मंहगाई भत्ता (रू0 15000 का 11%)	रू0 1650
	-----
	रू0 19,650
	-----

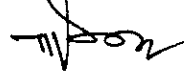
कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/XXVII(3) मं0पै0/2004 दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर-8 में भुगतान की प्रक्रिया के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1341/XXVII(3)मं0पै0/2004 दिनांक 6 अगस्त,2004 की तृतीय पंक्ति में इंगित कार्यालय ज्ञाप "दिनांक 6 जून,2004" के स्थान पर "दिनांक 9 जून,2004" पढी जाय। उक्त कार्यालय ज्ञाप के शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे।

राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त

संख्या- <sup>1358.</sup> (1) / XXVII(3) मं0पै0/2004 तददिनांक:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
  - 2- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
  - 3- सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
  - 4- सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
  - 5- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
  - 6- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
  - 7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल।
  - 8- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमाउँ मण्डल।
  - 9- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  - 10- रजिनल प्रविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर / देहरादून।
  - 11- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
  - 12- वित्त अधिकारी / कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
  - 13- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  - 14- निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।

आज्ञा से



(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव, वित्त।

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या।372'A'/xxvii(3)म.पें-5/2004  
देहरादून:दिनांक 07 अक्टूबर,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय-राज्य सरकार के पेन्शनर्स के पेन्शन में दिनांक 1.4.2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई राहत का मूल पेन्शन में विलय विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 का स्पष्टीकरण ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/xxvii(3) म.पें./2004 दिनांक 9 जून,2004 द्वारा 50 प्रतिशत की धनराशि का विलय मूल वेतन में किया गया है । विलय किये गये इस मंहगाई भत्ते को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए भी आगणित किये जाने की व्यवस्था उक्त कार्यालय ज्ञाप में की गयी है । दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों को पेन्शन निर्धारण में कोई हानि न हो इसके लिए विशेष व्यवस्था के रूप में मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ता 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन के सम्बन्ध में पेन्शन के परिकलन/आकलन के प्रयोजन हेतु मूल वेतन के रूप में माने जाने की व्यवस्था उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-5 में की गयी है ।

उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ता दिनांक 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन में पेन्शन के परिकलन/आकलन के लिए जोड़ा जायेगा अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों के पेन्शन आकलन हेतु 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन में मंहगाई भत्ता पूर्व अवधि से इस प्रकार जोड़ा जाएगा ताकि पेन्शन के आकलन हेतु 10 माह के मूल वेतन में मंहगाई भत्ता के 50 प्रतिशत की धनराशि सम्मिलित हो जाय तथा उक्त अवधि के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों को पेन्शन निर्धारण में कोई हानि न हो ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/xxvii(3) म.पें./2004 दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर-5 की व्यवस्था के अनुक्रम में यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है ।

राधा रतूड़ी  
सचिव

संख्या 372A/XXVII(3)म.पं.-5/2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल ।
- 3.सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।
- 4.सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
- 5.महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
- 6.निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
- 7.निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल ।
- 8.क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेन्शन, गढवाल/कुमायूँ मण्डल ।
- 9.महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय भवन,सहारपुर रोड माजरा,  
देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर  
के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- 10.रिजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/देहरादून ।
- 11.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
- 12.वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविधालय,उत्तरांचल ।
- 13.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस  
शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट  
करें ।
- 14.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

7/1/02

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या-1410/ XXVII(3)पे0/2004  
देहरादून,दिनांक 02 नवम्बर,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों  
आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1260/XXVII(3)पे0/2004, दिनांक 07 जून, 2004 द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2004 से स्वीकृत की गयी थी, जिसके उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1267/XXVII(3)म0पे0/2004, दिनांक 09 जून, 2004 के द्वारा 50 प्रतिशत महंगाई राहत के मूल पेंशन में जोड़े जाने के आदेश के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपरोक्त मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2004 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2004 से महंगाई राहत की एक और किस्त 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2004 से राहत की दर बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश न्यायालय के न्यायिधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अंतर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal  
Finance Section-3  
No.1410/XXVII(3)P/2004  
Dehradun, Dated: 2 November, 2004

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government civil/family pensioner.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.1260/XXVII(3)पे0/2004, dated 07 June, 2004 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 Jan, 2004 and Office Memorandum No.1267/XXVII(3)म0पे0/2004, dated 09 June, 2004 by which 50% dearness relief was added to pension as dearness pension. Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 3% with effect from 01 July, 2004 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 07 June, 2004 referred to above accordingly the rate of dearness relief of pension/family pension w.e.f. 01.07.2004 has risen to 14%.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institution aided from state under the Education/ Technical Education department whose pension/family pension is at par with the pensioners of the state government.

5. As per orders issued in O.M.No. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

राधा रतूड़ी  
सचिव।

संख्या- <sup>1411(C)</sup> / XXVII(3)P/2004, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून
2. समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

6. Others terms and conditions regarding old dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

Radha Raturi  
Secretary

No. 1411(C)/XXVII(3)P/2004, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. All Principal Secretaries/Secretaries Government of Uttaranchal.
2. All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
5. Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Mazra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8. Director, NIC, Dehradun.

By Order,  
(T.N.Singh)  
Addl. Secretary




उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या 1425XXVII(3)म.रा./2004  
देहरादून:दिनांक 11 जून, 2004

कार्यालय ज्ञाप

वित्त अनु-3 के कार्यालय ज्ञाप सं- 1267/XXVII (3) म0पे0/2004 दिनांक 9 जून, 2004 के प्रस्तर-3 में वर्तमान पेन्शन में देय 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई राहत को पेन्शन में विलय किया गया था और इस विषय में विभिन्न विभागों द्वारा जिज्ञासायें की जा रही हैं कि क्या पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेन्शन की वर्तमान समय में अधिकतम सीमा रू015,000 ही रहेगी अथवा यह भी इसी के अनुरूप पुनरीक्षित की जायेगी ।

2. अतः इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून, 2004 के प्रस्तर 3 में पेन्शन में 50 प्रतिशत मंहगाई राहत के विलय के उपरान्त अब पेन्शन की अधिकतम सीमा में भी (15,000 का 50 प्रतिशत अर्थात् रू07500) की वृद्धि करते हुए दिनांक 01/04/2004 से ही रू0 22,500 निर्धारित की जाती है (अर्थात् मूल पेन्शन रू015,000+मंहगाई राहत रू07500=कुल अधिकतम पेन्शन रू022,500) ।

3. समस्त पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी व बरिष्ठ कोषाधिकारी उक्तानुसार पेन्शन स्वीकृत करते हुए कोषागार में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।

  
(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त

संख्या 142/XXVII(3)म.रा./2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल ।
3. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
6. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
7. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़,माजरा,देहरादून  
को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य  
के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का  
कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल
13. उप निदेशक,राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ  
प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियां मुद्रित करा कर  
वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
14. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या 75XXVII(3)म.पे./2005  
देहरादून:दिनांक 17 फरवरी,2005

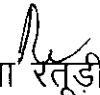
कार्यालय ज्ञाप

विषय:- राज्य के पेन्शनर्स के पेन्शन में दिनांक 1/4/04 से 50 प्रतिशत  
मंहगाई राहत का मूल वेतन में विलय के उपरान्त पेन्शन की न्यूनतम  
सीमा में संशोधन के विषय में स्पष्टीकरण:-

कार्यालय ज्ञाप सं0-1267/xxvii(3)म.पे./2004 दिनांक 9 जून,2004  
द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेन्शनर्स के मूल वेतन/पेन्शन में 50 प्रतिशत  
मंहगाई वेतन/राहत जोड़े जाने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0 1425/  
XXVII(3)म.पे./2004 दिनांक 11 नवम्बर,2004 द्वारा राज्य सरकार के पेन्शनर्स  
के पेन्शन की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु  
राज्य सरकार के पेन्शनर्स की पारिवारिक पेन्शन की न्यूनतम सीमा की स्थिति  
स्पष्ट करने हेतु कतिपय विभागों द्वारा जिज्ञासा की गयी है ।

2.इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि  
उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर-3 में राज्य के  
पेन्शनर्स के मूल पेन्शन का 50 प्रतिशत मंहगाई राहत को मूल पेन्शन में विलय  
किया जाय अतः राज्य सरकार के पेन्शनर्स की श्रेणी में पारिवारिक पेन्शनर्स भी  
शामिल होंगे तथा न्यूनतम पेन्शन हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेश के क्रम  
में रू0 1275 प्रतिमाह में भी 50 प्रतिशत मंहगाई राहत के विलय के उपरान्त  
आने वाली राशि पर शासन द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार  
अनुमन्य/पुनरीक्षित मंहगाई राहत का भुगतान का आगणन कर भुगतान किया  
जायेगा ।

3.समस्त पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी उक्तानुसार  
पेन्शन स्वीकृत/निधारित कर तदनुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।

  
राधा रतूड़ी  
सचिव,वित्त

संख्या 75, XXVII(3)म.पे. / 2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
7. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबैराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर / देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव


उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या 119 XXVII(3) / (6)मा. / 2005  
देहरादून: दिनांक 23 मार्च, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु दिनांक 1.4.04 से 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय में आगणन विषयक।

राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1/4/2004 से 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन में जोड़ने के विषय में कार्यालय ज्ञाप सं०-1267/XVII(3)म०पें/2004 दिनांक 9 जून, 2004 के संदर्भ में प्रदेश के वाहन चालकों को देय मानदेय के भुगतान में 50 प्रतिशत मूल वेतन जोड़कर मानदेय आगणित किये जाने के विषय में जिज्ञासायें की जा रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते को जोड़कर आंकलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ उक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरांत वित्तीय वर्ष में पूर्ण वर्ष की सेवा पर मूल वेतन यदि रू० 100 है इसमें 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते के रू० 50 के मर्जर (विनियम)के बाद अब रू० 150 के मूल वेतन के अनुसार चालकों को देय मानदेय का आगणन किया जायेगा।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा अग्रेत्तर अवधि हेतु उपरोक्तानुसार आगणित कर चालकों को देय मानदेय का भुगतान करने का कष्ट करें।

  
राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त

संख्या 119 XXVII(3) / (6)मा. / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
7. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबैराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर / देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से  
7/12  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या 16/XXVII(3)म.पे./2005  
देहरादून:दिनांक 30 अप्रैल,2005

कार्यालय ज्ञाप

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का यह कहन का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं01267/xxvii(3)म.पे./2004दिनांक 9जून,2004के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-1358/xxvii(3)म.पे./2004 दिनांक 27 अगस्त,2004 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स को वेतन/पेंशन में दिनांक 01-04-2004 से 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय हेतु चिकित्सकों के एन.पी.ए. के विषय में आंगणन हेतु उदाहरण को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

<u>मद का नाम</u>	<u>धनराशि</u>
मूल वेतन	रु0 10,000
एन.पी.ए.(स्लैब के अनुसार)	रु0 2,000
	रु0 12,000
मँहगाई वेतन (मूल वेतन+एन.पी.ए. का 50 प्रतिशत)	रु0 6,000
	रु0 18,000
मँहगाई भत्ता (मूल वेतन+एन.पी.ए.+वेतन का 14 प्रतिशत)	रु0 2,520
महायोग-	रु0 20,520

2.उपर्युक्तानुसार आगणित धनराशि में मूल वेतन तथा एन.पी.ए. की पूर्ण सीमा को संशोधित करके मूल वेतन+मँहगाई राहत+एन.पी.ए. के योग का अधिकतम भारत सरकार की बयवस्था के अनुरूप रु044250 प्रतिमाह होगी । उक्त तीनों का योग उक्त सीमा से अधिक नहीं होगा ।

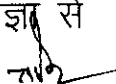
3.कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27अगस्त,2004 के आगणन के स्थान पर अब नया आगणन एन.पी.ए. हेतु उपरोक्तानुसार माना जायोगा ।

राधा रतूड़ी  
सचिव,वित्त

संख्या 68 XXVII(3) म.पे. / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
7. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबैराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर / देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से  
  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव



उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-3

संख्या 174(A)/XXVII(3)पें0/2005

देहरादून, 11 मई, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1411(1)पें0/XXVII(3)पें/2004, दिनांक 02 नवम्बर, 2004 द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 2004 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपरोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 नवम्बर, 2004 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2005 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जायी है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2005 से राहत की दर बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई है।

2-महंगाई राहत की ऐसी घनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3-यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6-महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Government of Uttaranchal

Finance Section-3

No. 174(A)/XXVII(3)P/2005

Dehradun, Dated : 11 May, 2005

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo no. 1411(1)/XXVII(3)P/2004, dated 02 November, 2004 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2004 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all Civil/Family Pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 3% (Three per cent) with effect from 01 Jan., 2005 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 02 November, 2004 referred to above accordingly the rate of dearness of Pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2005 has risen to 17%.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, Employees of local bodies and Public undertaking/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the Paying Authorities/Public Sector Banks.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

( 2 )

7-दिनांक 09.11.2000 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को उओप्रओ से अनुमन्य की जा रही महंगाई राहत के समतुल्य धनराशि देय होगी। कार्यालय ज्ञाप सं० 1411(1)/XXVII(3)पे०/2004, दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के द्वारा दिनांक 01.07.2004 से पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत में 3% (प्रतिशत) की अतिरिक्त महंगाई राहत को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01.07.2004 से 61% (प्रतिशत) से बढ़कर 64% (प्रतिशत) तथा दिनांक : 01.01.2005 से 3% (प्रतिशत) की अतिरिक्त महंगाई राहत को सम्मिलित करते हुए 67% (प्रतिशत) की दर से महंगाई राहत अनुमन्य की जाती है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,  
सचिव।

संख्या 174(A)/XXVII(3)पे०/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ, उत्तरांचल।
- 5-महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7-निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

आज्ञा से,

टी० एन० सिंह,  
अपर सचिव।

7. Pensioners who retired prior to 09.11.2000 would be eligible for dearness relief as admissible in Uttar Pradesh. Thus w.e.f. dated 01.07.2004 payable of additional dearness relief of 3% (per cent) would be 64% (per cent) instead of 61% (per cent) and w.e.f. dated 01.01.2005 that admissible dearness relief would be 67% (per cent) which includes an additional dearness relief of 3% (per cent) sanctioned by O.M.no., 1411(1)/XXVII(3)P/2004, dated 02 November, 2004.

By Order,

RADHA RATURI,  
Secretary.

No. 174(A)/XXVII(3)P/2005, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action :-

1. All Principal Secretaries/Secretaries.
2. All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director, Treasury and Pension, Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

T. N. SINGH,  
Addl. Secretary.

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3

संख्या- 471/xxvii(3)/2005  
देहरादून: दिनांक 07 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

**विषय:-** अविभाजित उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त/सेवा अवधि सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1484 xxvii(3)मं0रा0/2004, दिनांक: 15 दिसम्बर, 2004 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-05 xxvii(3)मं0रा0/2005, दिनांक: 17 जनवरी, 2005 में यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक उत्तर प्रदेश द्वारा 50 प्रतिशत महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित करने के आदेश निर्गत नहीं होते अथवा दोनों राज्यों के मध्य आपसी समझौता नहीं होता, उपरोक्त श्रेणी के पेंशनर्स को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1517/दरा-2005-308/2004, दिनांक: 22 सितम्बर, 2005 के द्वारा दिनांक: 01 अप्रैल, 2005 से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 09.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा की गयी सेवा पर अनुमन्य पेंशन पर उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक: 22 सितम्बर, 2005 के क्रम में दिनांक: 01 अप्रैल, 2005 से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित/विलयित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और उक्त के फलस्वरूप अब पेंशन तथा महंगाई पेंशन के योग पर दिनांक: 01 अप्रैल, 2005 से 17 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय होगी। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों को जिन्हें उत्तरांचल राज्य के कोषागारों से पेंशन भुगतान किये जाने की प्रक्रिया है, ऐसे पेंशनभोगियों को भी 01 अप्रैल, 2005 से उपरोक्त लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,  
इन्दु कुमार पान्डे  
प्रमुख सचिव।

संख्या-471 (1)/xxvii(3)/2005, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 2- महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 5- सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
- 6- सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
- 7- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 8- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
- 9- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- ~~10- महालेखाकार द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।~~
- 11- रिजनल प्रोविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
- 12- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 13- वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
- 14- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ।
- 15- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा

( टी0 एन0 सिंह )  
अपर सचिव वित्त।

उत्तरांचल शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
संख्या 9'A/XXVII(7)पै0/2005  
देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

Government of Uttaranchal  
Finance (G.R.-P.C.) Section -7  
NO-9'A/XXVII(7)P/2005  
Dehradun : Dated : 22 October, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-174(A)पै/XXVII(3)पै/2005, दिनांक: 11 मई, 2005 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2005 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 11 मई, 2005 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2005 से महंगाई राहत की एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जुलाई, 2005 से राहत की दर बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के सनान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्त्र है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 174(A)/XXVII(3)P/2005, dated: 11 May, 2005 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 Jan, 2005 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 4% (Four Percent) with effect from 01 July., 2005 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 11 May, 2005 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2005 has risen to 21%.


2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.


5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

झुङगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो सरु पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।


  
(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव

संख्या 9 A /XXVII(7)पें/2005, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तरांचल।
- 5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

आज्ञा, सी।  
  
(टी० एन० सिंह)  
अपर सचिव


6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

  
(Indu Kumar Pande)  
Principal Secretary

No. /XXVII(7)P/2005, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
- 5- Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary

वित्त (वे0आ0-सा0नि0)07  
संख्या: 01 / XXvii(7)म.कि. / 2006  
देहरादून:दिनांक:4 अप्रैल06

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-प्रदेश से बाहर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में महँगाई वेतन की देयता के विषय में निर्देश ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या:1267 / XXvii(3)म.पे0. / 2004दिनांक: 9 जून,2004 के द्वारा उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किये जाने के फलस्वरूप उक्त विलयित महँगाई भत्ते(महँगाई वेतन) को सेवानैवृत्तिक लाभ, जी0पी0एफ0 अशंदान एवं विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए आगणित किये जाने की व्यवस्था करते हुए परन्तु इसे एल0टी0सी0,यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण के समय देय यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता,मकान किराया भत्ते को मूल वेतन को ही आधार मानकर देने के निर्देश निर्गत किये गये थे ।

2.मकान किराये भत्ते की संशोधित दरों के विषय में शासनादेश संख्या:132 / वि0अनु0-3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था है कि ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों, जो राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा,जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो ।

3.प्रदेश से बाहर कार्यरत उत्तरांचल सरकार के राज्य कर्मचारियों के देय मकान किराया भत्ते की दर के निर्धारण के विषय में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय एवं उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर-6 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के क्रम में अद्योस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के बाहर नियुक्त राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों को मकान किराया भत्ता के आगणन हेतु 50 प्रतिशत महँगाई वेतन को वेतन में जोड़कर उस नगर में भारत सरकार के कर्मचारियों को जिस दर से मकान किराया भत्ता देय हो उसी दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक:9 जून,2004 के मकान किराया भत्ते विषयक प्राविधान केवल प्रदेश से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के लिए उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जाय ।

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
एस.एस. सचिव वित्त

संख्या: 01 / XXvii(7)म.कि. / 2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबैराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।
2. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
5. मुख्य स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली ।
6. सचिव, सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन, उत्तरांचल ।
7. भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली ।
8. इरला चेक अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से



(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव



उत्तरांचल शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनु-7  
संख्या: 12/XXvii(7)/2006  
देहरादून:दिनांक:15 अप्रैल,06

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं0189/XXvii(7)/2006 दि0:6 मार्च,2006 के द्वारा 9नवम्बर,2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स के विषय में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उक्त कार्यालय ज्ञाप के दूसरे प्रस्तर में उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण कतिपय पेंशनर संघों के द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप के स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 6 मार्च,2006 की व्यवस्था दिनांक: 9 नवम्बर,2000 के पूर्व उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त या उत्तरांचल राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स के लिए 50 प्रतिशत महंगाई राहत के मूल पेंशन में महंगाई पेंशन के रूप में मर्जर की सुविधा दिनांक 1 अप्रैल,2005 के स्थान पर प्राकल्पित आधार पर दिनांक 1 अप्रैल,2004 से ही अनुमन्य की जायेगी ।

2.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 मार्च,2006 की तृतीय पंक्ति में शब्द " मूल वेतन" के स्थान पर "मूल पेंशन" पढ़ा जाय।"

3.उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संशोधन के अलावा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 मार्च,2006 के शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे ।

भवदीय

राधा रतूड़ी  
सचिव


संख्या: 12(1)/XXvii(7)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल ।

4. सचिव,राज्यपाल,महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
6. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
7. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
8. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
9. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।
- 10.महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़, माजरा,  
देहरादून ।
- 12.रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।
- 13.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
- 14.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

संख्या 29(A)/XXVII(7)पें/2006  
देहरादून, 26 अप्रैल, 2006

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों  
आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के  
सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने  
का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 9(A)/  
XXVII(7)पें/2005, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 द्वारा मंहगाई  
राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 2005 से स्वीकृत की  
गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के  
समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता  
मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय  
ज्ञाप दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 में उल्लिखित दरों का  
अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2006 से मंहगाई राहत की  
एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने  
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार  
दिनांक 01 जनवरी, 2006 से राहत की दर बढ़कर 24  
प्रतिशत हो गई है।

2-मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये  
से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड  
कर दिया जाय।

3-यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,  
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों  
तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं  
होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से  
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के  
अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के  
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों  
के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू  
होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/  
दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत  
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान  
के लिये महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता  
नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत मंहगाई राहत का  
भुगतान कर दिया जायेगा।

6-मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य  
प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे,  
यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव।

Government of Uttaranchal

Finance (P.C.-G.R.) Section-7

No. 29(A)/XXVII(7)P/2006  
Dehradun, Dated April 26, 2006

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/  
Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this  
office memo no. 9(A)/XXVII(7)P/2005, dated October 22,  
2005 on the subject mentioned above sanctioning an  
installment of Dearness Relief with effect from July 01,  
2005 and to say that the Governor is pleased to revive  
the rates of dearness relief admissible to all Civil/Family  
Pensioners of this Government to compensate them for  
the rise in the cost of living beyond average Consumer  
Price Index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 3%  
(Three per cent) with effect from January 01, 2006 in  
supersession of the rates mentioned in the O.M. dated  
October 22, 2005 referred to above accordingly the rate  
of dearness of Pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2006  
has risen to 24%.

2. Payment of dearness relief involving a frac-  
tion of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the  
Judges of High Court, Chairman and Members of  
Uttaranchal Public Service Commission, Employees of  
local bodies and Public undertaking/Corporation etc. in  
respect of whom separate orders will have to be issued  
by respective departments.

4. These order will also be applicable to such  
teaching and non-teaching pensioners of Institutions  
aided from State under the Education/Technical Educa-  
tion Department whose Pension/Family Pension is at  
par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-  
10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General  
Authority is not necessary for payment of relief of pen-  
sion and as such the payment, of dearness relief as  
admissible under, this O.M. shall be made by the  
Paying Authorities/Public Sector Banks.

6. Others terms and conditions regarding of  
dearness relief laid down in earlier Government orders  
shall remain applicable as usual.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,  
Principal Secretary.

( 2 )

संख्या: 29(A)(1)/XXVII(7)पें / 2006. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- 5-महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7-निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

आज्ञा से,  
टी० एन० सिंह,  
अपर सचिव।

No. 29(A)(1)/XXVII(7)P/2006, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action :-

1. All Principal Secretaries/Secretaries.
2. All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director, Treasury and Pension, Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
T. N. SINGH,  
Addl. Secretary.

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) प्रमुख सचिव,  
वन एवं ग्राम्य विकास  
उत्तरांचल शासन।
- (2) प्रमुख सचिव,  
सिंचाई,  
उत्तरांचल शासन।
- (3) सचिव,  
लोक निर्माण विभाग  
उत्तरांचल शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 13 जुलाई, 2006

विषय : लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग  
जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान की पूर्व से व्यवस्था है, के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों  
को "उपदान संदाय अधिनियम, 1972" के अधीन उपदान संदाय के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग जहां पूर्व से कार्यप्रभारित कर्मचारी कार्यरत हैं, को उपदान के लाभ को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान दिये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विभागों की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों, जो राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पद को धारित न करते हों तथा जिन्हें किसी अन्य अधिनियम या नियम के अन्तर्गत उपदान अनुमन्य न हो और जिन पर "मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936" लागू होता हो, उन्हें अधिनियम के प्राविधानों के अधीन उपदान का संदाय किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त एवं अन्य विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को निम्न शर्तों के अधीन उपदान के संदाय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) दिनांक 1-02-1986 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्यप्रभारित कर्मियों को उपदान की सुविधा अनुमन्य होगी.
- (2) कार्यप्रभारित कर्मियों को एक वर्ष नियमति सेवा करने अथवा एक वर्ष में क्रम से कम 240 दिन कार्य करने पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।

- (3) कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।
- (4) दुर्घटना में विकलांग या मृत्यु होने पर 5 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (5) मजदूरी से "न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936" में परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है, तथा प्रतिवर्ष 15 दिन के मजदूरी के बराबर अन्तिम मजदूरी के आधार पर उपदान आगणित किये जाने की पात्रता होगी।
- (6) प्रतिवर्ष 15 दिन के आधार पर पूर्ण सेवा अवधि हेतु अधिकतम उपदान 20 माह के मजदूरी/वेतन से अधिक नहीं होगी।
- (7) उपदान की अनुमन्यता के लिए परिभाषायें, शर्तें एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिये "उपदान संदाय अधिनियम, 1972" के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- (8) इस श्रेणी की उपदान प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी या उसे देय कोई सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा सरकारी सेवा में नियमितीकरण होने पर यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक के अनुदान संख्या के उसी मुख्य/लघु/उपशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा, जहाँ से उसके मजदूरी/वेतन/पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है।

संलग्नक :- उपदान संदाय अधिनियम 1972 के आवश्यक अंश

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: 112 (1)/XXVII(7)/का0प्र0गै0/06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
- (2) निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
- (3) मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग व अन्य सम्बन्धित विभाग।
- (4) श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग।
- (5) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल।
- (6) लो0नि0 अनु-1/सिंचाई अनुभाग/ग्राम विकास अनुभाग एवं अन्य सम्बन्धित अनुभाग।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अं० 2/3/4
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा  
(टी0एन0रिंह)  
अपर सचिव वित्त

**Main Points of Payment of Gratuity Act, 1972**

1- Short title, extent, application and commencement –

(1) This Act may be called the Payment of Gratuity Act, 1972.

(2) It extends to the whole of India.

Provided that in so far as it relates to plantations or ports, it shall not extend to the state of Jammu and Kashmir.

(3) It shall apply to –

(a) Every factory, mine, oilfield, plantation, port and railway company;

(b) Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months;

(c) Such other establishments or class of establishments, in which ten or more employees are employed or were employed, on any day of the preceding twelve months, as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.

2- **Definitions** :- In this Act unless the context otherwise requires-

(b) "Completed year of Service" means continuous service for one year :

(c) "Continuous service" means uninterrupted service and includes service which is interrupted by sickness, accident, leave, lay-off, strike or a lock-out or cessation of work not due to any fault of the employee concerned, whether such uninterrupted or interrupted service was rendered before or after the commencement of this Act.

**Explanation – I** :- In this case of an employee who is not in uninterrupted service for one year, he shall be deemed to be in continuous service if he has been actually employed by an employer during the twelve months immediately preceding the year for not less than –

(i) 190 days, if employed below the ground in a mine or,

(ii) 240 days, in any other case, except when he was employed in a seasonal establishment.

**Explanation – II :-** An employee of a seasonal establishment shall be deemed to be in continuous service if he has actually worked for not less than seventy five percent of the number of days on which the establishment was in operation during the year ;

(h) "Family" in relation to an employee, shall be deemed to consist of –

- (i) In the case of a male employee; himself; his wife; his children; whether married or unmarried; his dependent parents and the widow and children of his predeceased son, if any;
- (ii) In the case of a female employee, herself her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the dependent parents of her husband and the widow and children of her predeceased son, if any;

Provided that if a female employee, by a notice in writing to the controlling authority, expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed, for the purposes of this Act, to be included in the family of such female employee unless the said notice is subsequently withdrawn by such female employee.

**Explanation –** Where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family, and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is, under the personal law of the person making such adoption, lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee;

(q) "retirement" means termination of the service of an employee otherwise than on superannuation.

(r) "superannuation" in relation to an employee, means, –

- (i) the attainment by the employee of such age as is fixed in the contract or conditions of service as the age on the attainment of which the employee shall vacate the employment; and
- (ii) in any other case, attainment by the employee of the age of fifty-eight years;

(s) "wages" means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or are payable to him in cash and includes dearness allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages and any other allowance.



#### **4. PAYMENT OF GRATUITY**

(1) Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years-

(a) on his superannuation, or

(b) on his retirement or, resignation, or

(c) on his death or disablement due to accident or disease :

Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement :

Provided further that in the case of death of the employee, gratuity payable to him shall be paid to his nominee, or if no nomination has been made to his heirs.

**Explanation :-** For the purpose of this section, disablement means such disablement as incapacitates an employee for the work which he was capable of performing before the accident or disease resulting in such disablement.

(2) For every completed year of service or part thereof in excess of six months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of fifteen days wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned :

Provided that in the case of a piece-rated employee, daily wages shall be computed on the average of the total wages received by him for a period of three months immediately preceding the termination of his employment, and, for this purpose, the wages paid for any overtime work shall not be taken into account :

Provided further that in the case of an employee employed in a seasonal establishment, the employer shall pay the gratuity at the rate of seven days' wages for each season.

(3) The amount of gratuity payable to an employee shall not exceed twenty month's wages.

(4) For the purpose of computing the gratuity payable to an employee who are employed, after his disablement, on reduced wages, his wages for the period preceding his disablement shall be taken to be the wages received by him during that period and his wages for the period subsequent to his disablement shall be taken to be the wages as so reduced.

(5) Nothing in this section shall effect the right of an employee to receive better terms of gratuity under any award of agreement or contract with the employer.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) –

(a) the gratuity of an employee, whose services have been terminated for any act, wilful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused;

(b) the gratuity payable to an employee shall be wholly forfeited :-

- (i) If the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part, or
- (ii) If the services of such employee have been terminated for any act which constitutes an offence involving moral turpitude provided, that such offence is committed by him in time course of his employment.

**NOTES :-** If a workmen is guilty of a serious misconduct such as acts of violence against the management or other employees or riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment, which though not directly causing damage, is conducive to grave indiscipline, then his gratuity can be forfeited in its entirety.

#### **6. NOMINATION :-**

- (1) Each employee, who has completed one year of service, shall make, within such time, in such form and in such manner, as may be prescribed, nomination for the purpose of the second provision to sub section (1) of Section – 4.
- (2) An employee may, in his nomination, distribute the amount of gratuity payable to him under this Act amongst more than one nominee.
- (3) If an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be made in favour of one or more members of his family, and any nomination made by such, employee in favour of person who is not a member of his family, shall be void.
- (4) If at the time of making a nomination the employee has no family, the nomination may be made in favour of any person or persons but if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith become invalid and the employee shall make, within such time as may be prescribed, a fresh nomination in favour of one or more members of his family.

- (5) A nomination may, subject to the provisions of sub sections (3), and (4), be modified by an employee at any time, after giving to his employer a written notice in such form and in such manner as may be prescribed, of his intention to do so.
- (6) If a nominee predeceased the employee, the interest of the nominee shall revert to the employee who shall make a fresh nomination, in the prescribed form, in respect of such interest.
- (7) Every nomination, fresh nomination or alteration of nomination, as the case may be, shall be sent by the employee to his employer, who shall keep the same in his safe custody.



(T. N. Singh)  
Additional Secretary  
Finance

उत्तरांचल शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
संख्या 215/XXVII (7) पे 2006  
देहरादून, दिनांक: 04 अक्टूबर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

ए- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ज- संसाधनी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-29(A)/XXVII(7)पे/2006, नं०: 26 अप्रैल 2006 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 26 अप्रैल, 2006 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2006 से महंगाई राहत की एक और किश्त 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दिये जाने की राहस्य स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जुलाई 2006 से राहत की दर बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal  
Finance (G.R.-P.C.) Section -7  
NO- 215/XXVII (7)P/2006  
Dehradun : Dated : 04 October, 2006

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/ Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.29(A)/XXVII(7)P/2006, dated: April 26, 2006 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from January 01, 2006 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 5% (Five Percent) with effect from July, 01 2006 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 26 April, 2006 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2006 has risen to 29 %.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to the teaching and non-teaching pensioners of aided Institute from the state fund under the education/ Technical Education Department of the state whose Pension/Family pension is as per the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6- Other terms and conditions regarding the dearness relief laid down in earlier Government orders shall be applicable as such.

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव

(Indu Kumar Pande)  
Principal Secretary

संख्या : 215 / XXVIII(7) पं / 2006, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
वित्त।

No: 215 / XXVII(7)P/2006, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- 5- महालेखाकार, उत्तरांचल, अंबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
- 5- Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

आज्ञा से,  
(टी० एन० सिंह)  
अपर सचिव

By Order,  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सारनि-के0आ0) अनुभाग-7  
संख्या 30/XXVII(7)पें/2007  
देहरादून, दिनांक 24 अप्रैल, 2007

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-215/XXVII(7)पें/2006, दिनांक: 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा महंगाई राहत की किस्त 01 जुलाई 2006 से स्वीकृति की गई थी, के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 04 अक्टूबर, 2006 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2007 से महंगाई राहत की एक किस्त 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जनवरी 2007 से राहत की दर 29 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttarakhand  
Finance (P.C.-G.R.) Section -7  
NO- 30/XXVII(7)P/2007  
Dehradun : Dated : 24 April, 2007

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.215/XXVII(7)P/2006, dated 04 October, 2006 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from July 01, 2006 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from January, 01 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 04 October 2006 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2007 has been risen from 29% to 35 %

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc, in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to the teaching and non-teaching pensioners of educational/Technical Institutions aided by State Government whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.


5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

  
(राधा रतूडी,  
सचिव

संख्या 30 /XXVII(7)पे/2007, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव

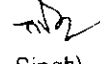
6- Other terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall be applicable as such.

  
Radha Raturi  
Secretary

No. 30 /XXVII(7)P/2007, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Buii Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of her states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
संख्या: 200 /XXVII(7)पै0/2007  
देहरादून, दिनांक: 01, अक्टूबर, 2007

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R.-P.C.) Section -7  
NO- 200 /XXVII(7)P/2007  
Dehradun : Dated : 01, October, 2007

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय:- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-30/XXVII(7)पै0/2007, दिनांक: 04 अक्टूबर, 2007 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2007 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 24 अप्रैल 2007 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2007 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जुलाई, 2007 से राहत की दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।  
3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 30/XXVII(7)P/2007, dated: 30April, 2007 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2007 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 July, 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 30April, 2007 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2007 has been risen to 41%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of education/ Technical Institutions aided by state Government whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain as such.

(राधा रतूडी)  
सचिव

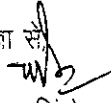
(Radha Raturi)  
Secretary



संख्या: 2804/XXVII(7)पें/2007, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव

No. 2804/XXVII(7)P/2007, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या 15 /XXVII (7)/2008  
देहरादून : दिनांक : 20 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय।

वित्त अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-119/XXVII(3)/(6) मा. /2005 दिनांक 23 मार्च 2005 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को जोड़कर आँकलित किया जाए। राजकीय वाहन चालक महासंघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 फरवरी 2008 में यह इंगित किया गया है कि उक्त शासनादेश में 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय के आगणन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः संशोधन आदेश निर्गत किया जाए।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1710/XXX(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर 2007 के क्रम में यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालकों से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों में कार्यरत वाहन चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाए।

2- शर्तें कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1710/XXX(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के अनुरूप ही रहेगी।

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

संख्या १५ /XXVII (7)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव

Office Memorandum

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-280/XXVII(7)पे0/2007, दिनांक: 01 अक्टूबर, 2007 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई 2007 से स्वीकृत की गई थी, के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 01 अक्टूबर 2007 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2008 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जनवरी, 2008 से राहत की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 280/XXVII(7)P/2007, dated: 01 October, 2007 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2007 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 July, 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 01 October, 2007 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2008 has been risen to 47%.

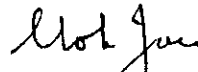
2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.


3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of education/ Technical Institutions aided by state Government whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain as such.

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव

  
(Alok Kumar Jain)  
Principal Secretary

संख्या: 14C1/XXVII(7)पै/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव

No.14C1/XXVII(7)P/2008, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4-Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा०नि०-वे०आ०) अनुभाग-7  
संख्या: 42०/XXVII(7) मं.रा./2008  
देहरादून, दिनांक: 27 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिए जाने विषयक राज्य की वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश सं० 419 / XXVII(7)पें/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा अनुमन्य किए गए वेतनमानों पर राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को निम्नानुसार महंगाई राहत अनुमन्य कराया जाय।

महंगाई राहत लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य महंगाई राहत का प्रतिशत
1.01.2006 से	महंगाई राहत देय नहीं है।
1.07.2006 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 02 प्रतिशत।
1.01.2007 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 06 प्रतिशत।
1.07.2007 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 09 प्रतिशत।
1.01.2008 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 12 प्रतिशत।
1.07.2008 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 16 प्रतिशत।

2. उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर महंगाई राहत का भुगतान पूर्व में शासनादेश सं० 29(A)/XXVII(7)पें/2006 दिनांक 26 अप्रैल, 2006 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से शासनादेश सं० 215/XXVII(7)पें/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा दिनांक 01.07.2006 से, शासनादेश 30/XXVII(7)पें/2007 दिनांक 24 अप्रैल, 2007 द्वारा दिनांक 01.01.2007 से, शासनादेश सं० 280/XXVII(7)पें/2007 दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 द्वारा दिनांक 01.07.2007 से एवं शासनादेश सं० 19/XXVII(7)पें/2008 दिनांक 21 मार्च, 2008 द्वारा दिनांक 01.01.2008 से स्वीकृत किए गए महंगाई राहत का समायोजन करने के उपरान्त किया जायेगा।


3. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन में मूल पेंशन का तात्पर्य निर्धारित रेडी रैकनर में बेसिक पेंशन तथा महंगाई पेंशन (डी०पी०)को जोड़कर जो धनराशि होगी उसे ही उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 के कालम-3 के अनुसार मूल पेंशन माना जायेगा।

4. महंगाई राहत के निर्धारित प्रतिशत में स्वतंत्र अनुमन्यता है इसे मूल नियम 9 (21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा।

5. महंगाई राहत के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे रुपये में मान लिया जायेगा।

6. दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु निर्गत शासनादेश सं० 421/XXVII(7)पें/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के साथ रेडी रैकनर की तालिका के कालम-3 में पुनरीक्षित पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत की दरें अनुमन्य होगी।

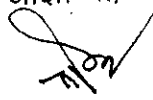
7. यदि कोई पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर दो पेंशन प्राप्त करने का हकदार है तब न्यूनतम पेंशन धनराशि रू० 3500 (रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र) हेतु दोनों पेंशन जोड़कर रू० 3500/- की धनराशि संज्ञान में ली जाय।

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव

संख्या: 420/XXVII(7) मं.रा./2008 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग) कमरा नं० 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001
6. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(टी०एन० सिंह)  
अपर सचिव

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:420/xxvii(7)म0रा0/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिनांक 1-7-2008 से महंगाई राहत 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 27 अक्टूबर, 2008 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2009 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जनवरी, 2009 से राहत की दर बढ़कर 22प्रतिशत हो गई है।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 420/XXVII(7)DR/2008, dated: 27 Oct, 2008 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2008 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 Jan, 2009 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 27 Oct, 2008 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2009 has risen to 22%.

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

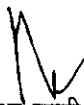
4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

  
राधा रतूड़ी  
सचिव

  
Radha Raturi  
Secretary



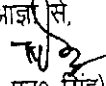
No. 153 /XXVII(7)P/2009, the date

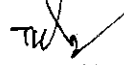
Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Divesion.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

क्रमांक: 153/XXVII(7)P/2009, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव

By Order,  
  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7  
संख्या 22/XXVII(7)/2009  
देहरादून, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2009

### कार्यालय ज्ञाप

विषय:- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1-1-2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न सेवानिवृत्त पेंशनर्स द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमाने की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक:1-1-2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में की गई जिज्ञासा के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है।

#### जिज्ञासायें

1.दिनांक 1-1-2006 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स के विषय में निर्गत शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर-6 में पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किये जाने की व्यवस्था कब से लागू की गई है, क्या यह प्रस्तर-1 में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के समान दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी समझे जाएंगे?

2.पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या 419/XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर-11 में वृद्ध पेंशनरों हेतु

#### स्पष्टीकरण

दिनांक1-1-2006 से पुनरीक्षित की गई पेंशन में जो भी नये नीतिगत निर्णय लिये गये हैं उक्त निर्णय से संबंधित प्रस्तर में उनके लागू किये जाने की तिथि स्पष्ट रूप से इंगित की गई है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन का शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 निर्गत होने के पूर्व चूँकि अनेक पेंशनर्स सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसीलिए शासनादेश का प्रस्तर-6(2) जो पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा के संबंध में है, की अंतिम पंक्ति से स्वतः स्पष्ट है कि पूर्ण पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष "तात्कालिक प्रभाव" अर्थात् शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि दिनांक 27 अक्टूबर,2008 से किया गया है।

उक्त प्रस्तर में आयु के प्रथम स्लैब में 80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम का अर्थ यह है कि 79 वर्ष पूर्ण होने पर 80वाँ वर्ष प्रारम्भ होने पर तथा 84 वर्ष के अंतिम

आलोच्य अवधि का आशय क्या है अर्थात् प्रथम स्लैब में 80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम का आशय क्या है अर्थात् 80 वर्ष प्रारम्भ होने पर देय होगी या 80 वर्ष पूर्ण होने पर अनुमन्य होगी।

3.80 वर्ष या इससे अधिक आयु की गणना किस प्रकार की जाएगी?

3.उपरोक्त कार्यवाही किस स्तर पर की जाएगी ?

दिन तक 20 प्रतिशत की पेंशन/पारिवारिक पेंशन अतिरिक्त रूप से देय होगी।

पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही वे मान्यता प्रदान की जाएगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेगे। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 1 जुलाई को एक वर्ष माना जाएगा, उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राईविंग लाईसेंस/

पैनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जायेगा और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जाएगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जाएगा।

80वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जाएगी।

4. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना में मंहगाई भत्ता किस प्रकार अनुमन्य होगा।

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जाएगा।

5. क्या 10 वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी देय होगी?

सी0एस0आर के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवक जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। शासनादेश दिनांक 17-10-2008 का प्रस्तर-6(1) स्वतः स्पष्ट है।

6. शासनादेश संख्या 413/XXVII  
(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,  
2008 के प्रस्तर 6(3) कि "अंतिम  
माह में आहरित वेतन जो 10 माह  
की औसत परिलब्धियां जो भी  
कर्मचारी को लाभप्रद हो, के 50  
प्रतिशत बराबर पेंशन अनुबन्ध  
होगी", उक्त व्यवस्था कब से लागू  
होगी

2- अतः समस्त पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के क्रम में उक्त निर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और यदि उक्त व्यवस्था के विपरीत व्यवस्था उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने के बाद नये पेंशन प्रकरणों में की जा चुकी है तो उक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही भी अविलम्ब सुनिश्चित की जाएगी।

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव/वित्त।

संख्या 21(1)/XXVII(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7  
संख्या:305/xxvii(7)/2009  
देहरादून, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1-1-2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न सेवानिवृत्त पेंशनर्स द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक:1-1-2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत का निदेश हुआ है।

1-दिनांक1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण:-

1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीकृता अधिकारी को सौंपा गया है। इस कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30-9-1988 अथवा उसके पूर्व की है एवं जिनके पेंशन प्राधिकार-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये गये हैं। ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य कोषाधिकारी स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप-1 पर वांछित सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करते हुए संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। अपितु संलग्न-प्रारूप-1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कोषागारों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1-9-2008 के प्रस्तर-42 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जाएगा।

2) शासनादेश संख्या 421/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिनांक:1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है। उक्त शासनादेश के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही

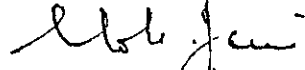
इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित बैंड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड-पे योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/-प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा भले ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृता अधिकारी कोई हो।

- 3) पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।
- 4) कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-2 पर पेंशनर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी। पेंशन स्वीकृत अधिकार उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेंगे।
- 5) 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जायेगी। पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त पेंशनर की जन्म तिथि के संबंध में पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पेंशनर/पारिवारिक

पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही वे मान्यता प्रदान की जाएगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेगें। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 1 जुलाई को एक वर्ष माना जाएगा, उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राईविंग लाईसेंस/पैनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जायेगा और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु सी०एम०ओ० द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जाएगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जाएगा।

- 6) शासनादेश संख्या27/xxvii(7)(स्प0-1)/2009 दिनांक13 फरवरी,2009 द्वारा दिनांक 31-8-2008 तक के समयमान वेतनमान पर भी ग्रेड पे की अनुमन्यता की गयी है अतः दिनांक 31-8-2008 तक अनुमन्य समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों में भी वेतनमान(पे बैंड का न्यूनतम एवं ग्रेड पे जोड़कर) के अर्हकारी सेवापूर्ण होने /33 वर्ष पर पेंशन का न्यूनतम 50 प्रतिशत या तदनुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य कराया गया है। इसके अनुसार दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामले में पेंशन का पुनरीक्षण सेवानिवृत्ति के समय 'धारित पद' के स्थान पर 'धारित' वेतनमान' के अनुसार किया जाएगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव/वित्त।



संख्या २०१६ (१) / XXVII(7) / 2009, तददिनांक

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूडी  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषय: दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या: 144/XXVII(7)म.म./2009 दिनांक 28 मई, 2009।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(6)/2009-ई-II(बी) दिनांक 18 सितम्बर, 2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के शासनादेश संख्या 144/XXVII(7)म0म0/2009 दिनांक 28 मई, 2009 द्वारा दिनांक 1-1-2009 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 22 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या: 144/XXVII(7)म0म0/2009 दिनांक 28 मई 2009 एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(6)/2009-ई-II(बी) दिनांक 18 सितम्बर, 2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-7-2009 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2009, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 नवम्बर, 2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,  
(राधा रतूडी)  
सचिव।

संख्या : 297 / xxvii(7)म.भ. / 2009 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),  
कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर / देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा स.  


(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

टी०एन०सिंह  
अपर सचिव,वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-7

देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01-01-2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:164/XXVII(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009।
- 2- भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-EII(बी) दिनांक 29 सितम्बर,2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे०आ०-सा०नि०) अनु०-7 के शासनादेश संख्या:164/XXVII(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009 द्वारा दिनांक 1-1-2009 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 64 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 26 अगस्त,2009 एवं 29सितम्बर,2009 के क्रम में दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांक: 01-07-2009 से मंहगाई भत्ते को 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई 2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2009 से 31 अक्टूबर,2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01नवम्बर,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियुक्त के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन०एस०सी० के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,  
21/10

(टी०एन०सिंह)

अपर सचिव।

संख्या : 299 / xxvii(7)म.भ./2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

11 - प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम अवरिक्त 2011/12

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

2-सचिव, शिक्षा,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषय:- राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:220/xxvii(3)अ0आ0/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में निदेशक, विधालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के पत्रांक अर्थ 5(क)8/1588/ग्रेच्युटी/2007-08 दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के दृष्टिगत राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग-अलग सेवानिवृत्ति लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2.उक्ताहनुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3.ग्रेच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिना के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।

4.60 वर्ष की आयु पूरान करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं लिया

जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांश तक, कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुर्ननियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जाएगी, तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर-520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5. उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा।

6. यह आदेश वि०वि० के शासनादेश सं०220/xxvii(3)अ.आ./2005 दिनांक 18 जून, 2005 के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार दिनांक 18, जून 2005 से ही लागू होगा।

भवदीया,

(राधा शर्मा)  
सचिव।

संख्या 310/xxvii(7)म.भ./2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. निदेशक, कोशागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा

(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
संख्या 298 / XXVII(7) म0रा0 / 2009  
देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R.-P.C.) Section -7  
NO-298 / XXVII(7)DR/2009  
Dehradun : Dated : 15 October, 2009

Office Memorandum

कार्यालय ज्ञाप  
विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को  
महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Subject : Grant of Dearness Relief to state  
Government Civil/Family Pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:153/xxvii(7)म0रा0/2009 दिनांक 28 मई, 2009 द्वारा दिनांक 1-1-2009 से महंगाई राहत 22 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 28 मई, 2009 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2009 से महंगाई राहत की एक और किश्त 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जुलाई, 2009 से राहत की दर बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई है।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 153/XXVII(7)DR/2009, dated: 28, May 2009 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2009 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 5% (Five Percent) with effect from 01 July, 2009 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 28, May 2009 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2009 has risen to 27%.

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

  
रishi Raut  
सचिव

  
Radha Raut  
Secretary



संख्या: 298/XXVII(7)पै/2009, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव

No 298/XXVII(7)P/2009, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary